RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-04, अंक - 47 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 25 अगस्त 2022 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सुविचार

जीतने वाले अगल चीजें नहीं करते वो चीजों को अगल तरह से करते है।

शिव खेड़ा

जब-जब लोगों ने अपनी जान गवांई, तब-तब ही सरकार हरकत में आई , बाकी दिनों में स्थिति 'ढाक के तीन पात'

माही की गूंज, संजय भटेवरा

– ट्रक से भीडा वाहन जिसमें 15 स्कूली बच्चें थे सवार चार की मौके पर हुई थी मौत।

चार मासुम, भाव्याशं पिता सतिश जैन, सुमित पिता सुरेश, उमा पिता ईश्वरलाल, इनाया पिता रमेश नादेड की अर्थिया एक साथ उठी थी जिसके बाद सरकार व तन्त्र कर रही अपनी सजगता का ढ़कोसला।

झाबुआ। जब-जब प्रदेश में किसी तरह के गंभीर सड़क हादसे होते है और कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते है, तब-तब सरकार हरकत में आकर ''सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटने का काम करती है'', यह कोई आज की बात नहीं है। सरकार और उसका तंत्र तभी हरकत में आता है जब उस पर सवालिया निशान लगने लगते है। ऐसा प्रतीत होता है मानों यह सरकार और उसके तंत्र के खून में ही है कि, जब तक किसी की जान नहीं जाती तब तक जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दिया जाए। जब भी प्रदेश में इस तरह के गंभीर हादसों में लोगों की जान जाती है, तो वही खून में शामिल बीमारी बाहर आ जाती और एक हल्ला पूरे प्रदेश में हो जाता वह भी यह दिखाने के लिए कि, सरकार इन मुद्दों पर कितनी सजग और मुस्तैद है।

हाल ही में पिछले दिनों उज्जैन जिले के उन्हैल में स्कूली बच्चों से भरा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें चार नौनिहालों ने अपनी जान की आहुति दी, 12 बच्चे इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। तब जाकर सरकार व उसके तंत्र की नींद खुली और पूरे प्रदेश में जैसे हल्ला सा मच गया। अब पूरे प्रदेश में स्कूली बच्चों का परिवहन करने वाले वाहनों पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। या यूं कहें कि, सरकार व उसका तंत्र अपनी नाकामी, गलतियों और विफलता को छुपाने के लिए फिर एक अभियान लेकर सड़कों पर उतर आया है। वैसे वर्ष के बाकी दिनों में स्थिति ''ढाक के तीन पात'' ही साबित होती नजर आती है।

यूं तो वर्ष भर सरकार व उसका तंत्र सड़क दुर्घटनाओं को लेकर कभी सजक दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब-जब कोई गंभीर सड़क दुर्घटनाएं सरकार व उसके तंत्र की पोल खोलती दिखाई पड़ती तो सारे बागड़ बिल्ले अपना भोपू लेकर सड़क पर उतर आते और कार्रवाई के नाम पर ढकोसला शुरू हो जाता। हालांकि यह ढकोसला दो-चार दिन या एक सप्ताह से अधिक समय का नहीं होता, उसके बाद सरकार और उसके तंत्र की सारी सजगता चादर तान कर सो जाती है।

हर वर्ष स्कूली विद्यार्थियों के साथ कोई ना कोई बड़ा हादसा सामने आते रहे है और कारण भी समय के साथ सामने आते रहे है। लेकिन इन दुर्घटनाओं को लेकर सरकार द्वारा किए गए सारे करमकांड सिफर ही नजर आते रहे है। नौनिहालों के साथ होती इन दुर्घटनाओं का अब तक किसी तरह का कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण सरकार की नाकामी को ही माना जा सकता है। हालांकि अभिभावकों में इस हेतु जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। वर्तमान में स्थिति कुछ ऐसी है कि, पूरे प्रदेश में स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वाले वाहनों का किसी प्रकार का डाटा अब तक सरकार के पास नहीं है। हालात इतने गंभीर है कि, बिना परमिट के कंडम वाहनों में बच्चों को सफर कराया जा रहा है। इस तरह के वाहनों के पास पर्याप्त दस्तावेज भी मौजूद नहीं होते है। कहीं बीमा खत्म तो कहीं परमीट नदारद, वाहनों की हालत भी ठीक नहीं और उस पर सितम यह कि बिन वैध दस्तावेज के अवैध गैस वाहनों में बच्चों को भेड़-बकरी की तरह भरकर स्कूल लाया ले जाया जाता है। अब जबकि प्रदेश में एक और हादसे में चार स्कूली बच्चों ने अपनी जान गवाई है, तो सरकार व उसका तंत्र फिर सड़कों पर आ गया है। चार बच्चों की जान जाने के बाद कई अभियान चलाए जा रहे है, तो कही सड़क जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। मासूम नौनिहालों की जान भी इन अभियानों व जागरूकता सप्ताह के बाद व्यर्थ ही साबित हो जाएगी, जैसा कि पूर्व के हादसों में स्कूली बच्चों के साथ होती आई है।

उज्जैन जिले के उन्हैल में हुई इस घटना के बाद मध्यप्रदेश के पश्चिमी छोर पर बसे आदिवासी बाहुल जिले में भी प्रशासन हरकत में आया और परिवहन विभाग व यातायात अमले ने ढकोसले की शुरूआत कर दी है। आए दिन अखबारों की सुर्खियों में रहने वाला परिवहन विभाग अपने कर्तव्य की इतिश्री करने के लिए सड़कों पर उतर कर स्कूली बच्चों का परिवहन करने वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई करता दिखाई दे रहा है। तो यातायात अमला भी यातायात सप्ताह व सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान मनाता नजर आ रहा है। यातायात अमला शहर में घूम रहे दो पहियां वाहनों पर चालानी कार्रवाई भी कर रहा है। हालांकि यातायात अमला आम दिनों में भी यही काम करते अक्सर दिखाई पड़ता है, लेकिन परिणाम के नाम पर अब तक स्थिति शुन्य ही है। हां यह जरूर है कि परिवहन विभाग का राजस्व वसूली का टारगेट जरूर पूरा हो जाता है।

परिवहन विभाग के आला अधिकारी की बात की जाए तो इनकी भी बात निराली ही है। आदिवासी बाहुल जिले से कई अवैध बसें ग्रामीण आदिवासियों को भर कर मनमाने किराए में अन्य राज्य के लिए परिवहन करती है। लेकिन आरटीओ मेडम मोहटा को यह दिखाई नहीं देता है। जिले में चलने वाली सवारी बसों पर भी अब तक किराया सूची चस्पा नहीं हो पाई है, मगर इस आमजन से जुड़े मुद्दे से भी मेडम को कोई मतलब नहीं है। अब मेडम का इन मुद्दों को लेकर कोई रूची ना लेना बड़ी गठजोड़ की तरफ ही इशारा करता है। हालांकि दलालों की माने तो जिले से अन्य प्रदेशों में सवारियों का परिवहन करने वाली अवैध बस मालिकों द्वारा मेडम की मांग अच्छी तरह से भरी जाती और मुंह भी मीठा कराया जाता रहता है। यही हालत जिले में चलने वाली यात्री बसों के मालिकों का भी है जिसके चलते वे यात्रियों से मनमाना किराया वसूल कर रहे है। मतलब सीधा सा है कि बस मालिकों की अवैध कमाई में आरटीओं का भी हिस्सा फिक्स रहता है।

23 अगस्त को मेघनगर के एक निजी स्कूल में बच्चों का परिहवन करते हुए पांच अवैध वाहनों पर एसडीएम के नेतृत्व में आरटीओ अमले ने चालानी कार्रवाई की। यह एक विचारणीय प्रश्न है कि, जब जिले के छोटे से कस्बे के एक स्कूल में बच्चों का परिवहन करते पांच अवैध वाहन हो सकते है, तो जिले में चल रही तमाम निजी शैक्षणिक संस्थाओं के कितनें अवैध वाहन बच्चों के परिवहन में इस्तेमाल होते होंगे...? हालांकि यह एक कड़वा सत्य है कि निजी शैक्षणिक संस्थाएं इन अवैध वाहनों से किसी तरह का संबंध होने से इंकार कर दे। मगर इस तरह के वाहनों में विद्यार्थियों का परिवहन तो होता ही है। इस तरह के वाहनों में बच्चों को स्कूल भेजना पालकों की मजबूरी भी कही जा सकती है। क्योंकि निजी शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चों के ट्रेवलिंग का खर्च बहुत अधिक होता है। उदाहरण के तौर पर जहां यही अवैध वाहन प्रति बच्चे को स्कूल लाने ले जाने का प्रतिमाह 6 सौ से 1 हजार रुपये तक अभिभावकों से लेते है। वहीं निजी शैक्षणिक संस्थाओं के वाहनों में यह फीस दो गुनी के करीब अभिभावकों से वूसली जाती है। यही सबसे बड़ा कारण है कि अभिभावक महंगाई के इस दौर में दो पैसे बचाने के चक्कर में इन अवैध स्कूली वाहनों में अपने बच्चों को स्कूल भेजते है।

अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि, क्या परिवहन विभाग या अधिकारी ने कभी यह कोशिश की कि निजी स्कूलों में चलने वाले स्कूली वाहनों का किराया किस तरह से वसूला जाता है या स्कूल के निजी वाहनों में सुरक्षा के वे सभी मापदंड पूरे किये जाते है जो बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी है...? कहीं निजी शैक्षणिक संस्थाएं अभिभावकों से बच्चों के ट्रेवलिंग चार्ज के नाम पर बहुत ज्यादा खर्च तो नहीं ले रही है...? इस तरह के सवालों का जवाब शायद परिवहन विभाग के आला अधिकारी के पास नहीं होगा। मगर हालात कुछ ऐसे है कि निजी शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे वाहनों का खर्च इतना अधिक है कि अगर अभिभावक अपने पर्सनल वाहन से भी बच्चों को स्कूल छोड़े तो वह भी सस्ता ही पड़ेगा।

कुल मिलाकर जब-जब स्कूली बच्चे सड़क हादसों का शिकार होंगे या जब-जब बड़ी सड़क दुर्घटनाएं सामने आएंगी तब-तब सरकार व उसका तंत्र अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सड़कों पर उतरेगा और कुछ ही दिनों की कार्रवाई के बाद अपने कर्तव्य की इतिश्री करते हुए फिर से चादर तान कर सो जाएगा। जबकि परिवहन अमले को अपनी कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन करते हुए लगातार इस तरह की कार्रवाई करते रहना चाहिए।

केजरीवाल ने गडकरी के नाम पर अपने ही एमएलए को करवाए थे फोन- योगेंद्र यादव

नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इन दिनों सीबीआई के रडार पर हैं। दिल्ली में शराब नीति को लेकर चल रहे विवाद पर आप के पूर्व नेता योगेंद्र यादव ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने परमजीत कात्याल के एक पुराने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी थी।

योगेंद्र यादव ने ट्वीट कर कहा, परमजीत जी ने 7 वर्ष पहले इस घटना के बारे में मुझे जानकारी दी थी। तब मैंने पूछताछ की और पाया कि उनकी बात पूरी तरह सच है। अरविंद केजरीवाल के आदेश पर दिसंबर 2013 में अपने ही एमएलए को भाजपा के नाम पर फोन करवाए गए थे। ऐसी करतूतों के कारण हम लोगों का आप नेतृत्व से मोहभंग हुआ था। शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच चल रही तनातनी के बीच भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने मंगलवार की रात ट्विटर पर एक नया वीडियो शेयर किया। उन्होंने दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी पर तंज कसा है। अमित मालवीय ने अरविंद केजरीवाल से स्पष्टीकरण की भी मांग की कि जांच के आदेश के तुरंत बाद नई शराब आबकारी नीति को क्यों उलट दिया गया।

अमित मालवीय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, अगर अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को पद्म विभूषण, सिसोदिया को भारत रत्न और खुद को ऑस्कर के लिए नामांकित करते हैं, तो उन्हें यह बताना चाहिए कि जांच के आदेश के तुरंत बाद नई शराब आबकारी नीति को क्यों उलट दिया गया। इसके लिए कितनी रिश्वत मिली। दिल्ली सरकार को कुल कितना नुकसान हुआ?

अमित मालवीय ने एक पुराना वीडियो भी साझा किया जो जाहिर तौर पर आप के पूर्व सचिव परमजीत सिंह कात्याल का है। इस वीडियो में उन्हें अरविंद केजरीवाल का मज़ाक उड़ाते हुए देखा जा सकता है। इसमें उन्होंने भाजपा पर भाजपा के 35 विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। परमजीत कात्याल ने दावा किया कि उन्हें और अन्य को अरुण जेटली और नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं के नाम पर आप विधायकों को पैसे के बदले पार्टी से अलग होने का ऑफर देने के लिए कहा गया था।

गड्ढे के विवाद में चचेरे भाइयों ने कर दी हत्या, दो भाइयों और उनके पिता के खिलाफ मामला दर्ज

माही की गूंज, रतलाम।

पैतृक जमीन और घर के पीछे गड्ढे में पानी भरने के मामूली विवाद ने रिश्तों का खून कर दिया गया। चचेरे भाइयों और उनके पिता ने मिलकर एक युवक को चाकू और लोहे के पाईप से इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई। घटना मंगलवार की रात करीब साढ़े दस बजे की है। मृतक युवक का शव रात में जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस ने प्रारंभिक रूप से तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बिलपांक थाना प्रभारी दीपक शेजवार ने बताया कि, घनश्याम पाटीदार पिता गोविंद पाटीदार 20 निवासी सिमलावदा की बीती रात हत्या हुई है। मृतक युवक बदनावर में किसी दुकान पर काम करता था और वह रात आठ बजे दुकान से घर लौटा था। घर पर परिवार और उसके चचेरे भाइयों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। विवाद के दौरान वह भी वहां पहुंचा तो मामला बढ़ गया और चचेरे भाइयों दीपक पिता गोपाल पाटीदार, उसके भाई मनोहर पिता गोपाल पाटीदार और गोपाल पिता शंकरलाल पाटीदार ने मिलकर उस पर चाकू और लोहे के पाईप से हमला कर दिया। बीच बचाव करने गए घनश्याम के मामा के साथ भी मारपीट की।

यह था विवाद

विवाद का कारण पैसा और शौचालय के गंदे पानी को लेकर हुआ। मंगलवार की रात में विवाद हुआ था। पूर्व से ही इन दोनों परिवारों के बीच पैतृक जमीन को बेचने व रुपयों को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जाता है कि, मृतक घनश्याम के बड़े पापा गोपाल पाटीदार ने जमीन बेची थी। जमीन के रुपयों का बंटवारा होना था। गोपाल ने छोटे भाई घनश्याम के पिता गोविंद को कुछ पैसा देने के बाद पैसा नही दिया। यह मामला चल रहा था और बीच-बीच में इनके बीच में विवाद होते रहे हैं। अभी ताजा मामला घर के पीछे बने सीवरेज के गड्ढे को लेकर हुआ। दोनों घरों के बीच में एक ही गड्ढा है और इसमें पानी भर जाने को लेकर दोनों परिवार एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहते। यह विवाद मंगलवार की रात को बढ़ गया और मामुली विवाद में घनश्याम की हत्या कर दी।

सीएम ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर काम करने के दिए निर्देश, किया हवाई सर्वे

भोपाल।

मध्य प्रदेश में बाढ़ से हुई क्षति के बाद व्यवस्थाओं को पुनर्स्थापित करने की कार्ययोजना तैयार करने के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाई लेवल बैठक ली। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर, बांधो की जानकारी की समीक्षा की।

बैठक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी उतरने के बाद वहां आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि, युद्ध स्तर पर काम करना हैं। बैठक में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट समेत संबंधित विभाग के आला अधिकारी और प्रमुख सचिव उपस्थित रहें।

अधिकारियों को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने और बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, कई जगह बिजली के खंबे टूट गए हैं, ट्रांसफार्मर डूबे हुए है, इन्हे ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर जुटें। बीमारी न फैले, इसके लिए दवा छिड़काव से लेकर साफ-सफाई कराने और मेडिकल टीम गठित कर गांव और शहर पहुंचकर, आवश्यक दवाएं बांटे।

सीएम ने बारिश के दौरान खराब हुई फसलों का नुकसान, मवेशियों का नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि, ये चुनौतियां है, हम सभी टीम बनाकर लोगो की मदद के लिए आज से लगे। जो भी अतिरिक्त अमला लगना है, विभाग समीक्षा कर आज से ही प्रभावित क्षेत्रों में भेजे। मैन पावर, मशीन जो भी लगना है लगाए। आरबीसी 6(4) के अंतर्गत जो भी नुकसान का सर्वे कर सहायता करनी है उसे करेंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को विदिशा शहर और कुरवाई क्षेत्र का दौरा किया। साथ ही चंबल क्षेत्र में भी बाढ़ राहत कार्यो का जायजा लिया और भिंड, मुरैना जिलों का हवाई सर्वे भी किया। उल्लेखनीय है कि, मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक निरस्त की थी और विदिशा जिले के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन देखा था। इसके साथ ही 5 जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया था।

2024 तक सोनिया गांधी ही बनी रहेंगी कांग्रेस अध्यक्ष

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक कोई चेहरा सामने नहीं आया है। राहुल गांधी के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है और कांग्रेसी उनसे पद संभालने की अपील भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस पर अनिच्छा जाहिर की है। इस बीच कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि, पार्टी के सीनियर नेताओं ने सोनिया गांधी से ही अपील की है कि वह 2024 तक पद पर बनी रहें। इन नेताओं का कहना है कि, गांधी परिवार के अलावा कोई भी पार्टी को एकजुट नहीं रख सकता। ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी टूट सकती है और प्रियंका गांधी को 2024 के बाद कमान सौंप दी जाए।

इस बीच सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत के नाम का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि, यदि गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनता है तो फिर अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि, दो नेताओं के साथ बैठक में भी अशोक गहलोत ने यह बात कही है। इस बीच राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तीनों ही इलाज के लिए विदेश जाने वाले हैं। दरअसल सोनिया गांधी का चेकअप होने वाला है और इस दौरान राहुल और प्रियंका भी उनके साथ रहेंगे। अगले कुछ दिनों में ही कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए शेड्यूल का ऐलान होने वाला है। इस संबंध में 28 अगस्त को मीटिंग होने वाली है।

गांधी परिवार से किसी के आगे न आने के चलते अब अशोक गहलोत का नाम ही सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल, कुमारी शैलजा, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेश बघेल के नाम भी अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा में हैं। कांग्रेस ने बताया था कि, अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू होगी और 20 सितंबर तक चलेगी। हालांकि अब तक राहुल गांधी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। किसी और नेता का नाम भी सामने नहीं आया है। इस बीच कांग्रेस ने 7 सितंबर से कन्याकुमारी से यात्रा निकालने का फैसला लिया है। यह मार्च 148 दिनों तक चलेगा और कश्मीर तक जाएगा। 5 महीने की इस यात्रा में 3 हजार 500 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। हर दिन 25 किलोमीटर यात्रा चलेगी।

गहलोत ने किया इनकार

23 अगस्त को सोनिया गांधी और अशोक गहलोत की मुलाकात के बाद खबर आई थी कि सोनिया गांधी ने गहलोत से पार्टी का नेतृत्व संभालने के लिए कहा है।

इस तरह की रिपोर्ट को खारिज करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें भी मीडिया से पता चला है। गहलोत ने कहा, मैं इस बारे में नहीं जानता। मुझे जो काम दिए गए हैं, मैं उन कर्तव्यों को पूरा कर रहा हूं।

पुलिस है कि मानती नहीं, सटोरिए है कि मनमानी से बाज आते नहीं

सट्टा किंग मलिक पर पुलिस कब कसेगी शिकंजा...?

माही की गूंज, शुजालपुर। अजय राज केवट

शुजालपुर पुलिस और सटोरियों के बीच में इन दिनों तू-डाल-डाल, मैं पात-पात का करवा चल रहा है। गली-मोहल्ले के बेरोजगार व कम पढ़े-लिखे युवक सटोरियों के निशाने पर है। सट्टा लिखने वाले गुर्गों को नहीं मालूम कि मुख्य सटोरियों का बॉस आखिर कौन है। नशीले पदार्थ के लालच और कमीशन के नाम पर सटोरिए दाने डाल रहे है।

माही की गूंज सरोकार और सामाजिक दायित्व को निभाते हुए समाज में फैले असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ खबरों को प्रकाशित कर शासन-प्रशासन के संज्ञान में लाने की अहम भूमिका निभा रहा है। शुजालपुर में निम्न और मध्यमवर्गीय परिवार के साथ-साथ गरीब तबकों के लोगों में सट्टा की खुमारी ऐसी छाई है कि कामधंधा छोडकर ओपन-टू-क्लोज का दिवाना हो चुका है। इसकी तस्वीर सब्जी मार्केट मलिक के यहा साफ देखी जा सकती है। सुबह उठते ही पुराने रिकार्ड लेकर लोग सट्टा का अचूक आंकड़ा निकालते दिख जाते है, ओर क्या आया, क्या खुला, जैसे डायलॉग सुन सकते है। लोगों को शहर और घर में क्या हो रहा है क्या सामान नहीं है, इसकी चिंता करने के बजाय ओपन-टू-क्लोज की दिवानगी सब्जी मार्केट मलिक और गोपाल डेरी के साईड में शाकिर यहा देखी जा सकती है। पुलिस का खुफिया तंत्र लगातार सटोरियों की सूचना देकर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। उसके बाद भी सटोरियों और पुलिस में लुकाछिपी का खेल बेखौफ चल रहा है।

पुलिस है कि कार्रवाई से मानती नहीं और सटोरिए है कि मनमानी से बाज आते नहीं के तर्ज पर खेल चल रहा है। पुलिस कार्रवाई का तो सटोरियों को खौफ ही नहीं रहा है, कारण जगजाहिर है, छुटभैया नेता उनके संरक्षक जो है, जो थाने से छुड़ाने का साल भर का ठेका ले रखे हैं। लग्जरी लाइफ जीने वाले छुटभैया नेता जिसे कभी साइकिल भी नसीब नहीं था, वे आज कार और स्कार्पियो में घूम रहे है। जबकि सभी को मालूम है कि उन छुटभैया नेताओं का फाइनेंसियल बैकग्राउंड आज से पांच वर्ष पहले क्या था, और आज क्या है। जमीन दलाली और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले छुटभैया नेता दिहाड़ी कमाई के लिए सटोरियों को संरक्षण दे रखे है जिससे उनकी गाड़ी का पेट्रोल खर्चा और रात को खाने-पीने का इंतजाम सटोरियों के बॉस मलिक ही करता है। बड़े बड़े सटोरियों से हाथ मिलाकर राज्य स्तर पर सट्टा का संचालन को अंजाम दे रहे है। पुलिस को जहां-जहां सट्टा लिखने की सूचना मिलती है लगातार कार्रवाई भी कर रही है, उसके बाद भी सटोरियों में पुलिसिया खौफ कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। पुलिस के बड़े अधिकारियों के सख्त निर्देश के बाद भी शुजालपुर में सट्टा बंद नहीं हो सका। पुलिस भी इन कमियों को जानती है, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते मजबूर है, छोटे-मोटे गुर्गों को पकड़ कर खाना पूर्ति कर रही है। जबकि सट्टा किंग मलिक आलीशान आफिस बनाकर लक्जरी कार में नेताओं के साथ उठ बैठ रहे है । ऐसी स्थिति में पुलिस उन सटोरियों के गिरेबान पर हाथ डाले तो कैसे डाले, क्योंकि उसके पास पुख्ता सबूत ही नहीं है, पुलिस ने आज तक जितने भी सटोरियों को पकड़ा है किसी ने भी सट्टा किंग मलिक का नाम नहीं बताया है। ये सटोरिए तो निजी मुचलके पर थाने से ही छूट कर फिर सट्टा में लिप्त हो जाते है। क्योंकि सट्टा में ही रोज एक हजार की कमाई करने की आदत लग चुकी है। दिहाड़ी मजदूरी में किसी के दुकान में काम करने पर मात्र 300 रुपए मिलते है, इसलिए रोज एक हजार रुपए कमीशन के लिए सट्टा को ही मुख्य रोजगार बना रखा है।

पूरे सातों दिनों सट्टा का खेल शुजालपुर में चल रहा है, मलिक और शाकीर गैंग अपना सट्टा-कारोबार चलने के लिए रोज नए-नए तरीके का इस्तेमाल कर रहे है।

कोई रोक-टोक नहीं

शहर के कई क्षेत्रों में सट्टे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। विश्वसनीय सूत्रों की मानें तो पूरा मामला जान कर भी स्थानीय पुलिस मौन धारण किए हुए है। पूरे शहर को सट्टे ने अपनी चपेट में ले लिया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग अब खुलेआम सट्टा खेल रहे हैं और उनमें पुलिस का भी कोई डर नहीं नजर आता। वहीं पुलिस भी इस पूरे मामले पर अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। शहर की तंग गलियों में काफी लोग सट्टे के धंधे में लगे हुए हैं। वहीं हालात देखकर लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि जिस तरह लोग खुलेआम सट्टा चलने लगा है, इसकी जानकारी पुलिस को होते हुए भी कोई कार्यवाई नहीं कि जाती हैं।

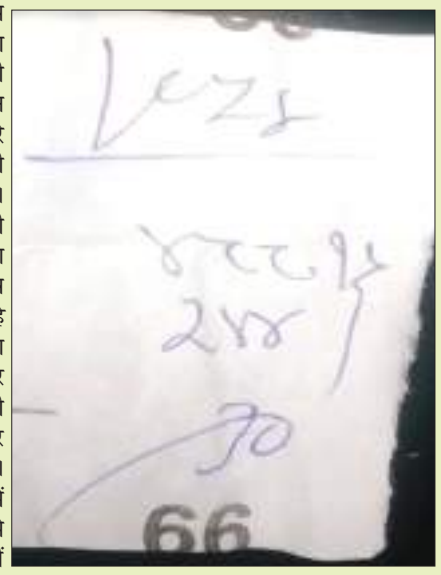

कानून व्यवस्था बिगाड़ ने वाले सक्रिय

जिले में कानून व्यवस्था को बिगाडने् वाले सटोरियों का गिरोह सक्रिय है, जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के बाद भी पुलिस का भय नहीं है। पहले तो कभी कभार एक दो छोटे प्रकरण बनाकर खानापूर्ति कर दी जाती थी, लेकिन सट्टे के कारोबारियो के हौसले बुलंद हैं। वे अपने काम को खुलेआम संचालित कर रहे हैं। सट्टे के इस कारोबार में जहां एक तरफ सटोरिया मालामाल हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ कई घर बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके है लेकिन स्थानीय पुलिस मानो कान में तेल डाल कर बैठी हो और वह सटोरियों पर मेहरबान नजर आ रही है।

पुलिस भी इस बात से बेखबर है और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि पुलिस इनके ठिकानों में छापा मारने जाते भी है तो मलिक ने कई जगह नेटवर्क फैला रखा है। जिससे पुलिस की कार्रवाई की सूचना मिल जाती है ओर ये अंडरग्राउंड हो जाते है। हर गलियों में अपने गुर्गे बिठाकर रखे हैं। । और सट्टा खिलाने के लिए मलिक अपने गुर्गों का। इस मास्टर माइंड अपराधियों तक पुलिस का पहुंच पाना मुश्किल है क्योंकि मलिक ने अपने सूत्रों हर कोने कोने पर खड़ा कर रखा है जिससे पुलिस की हर खबर आसानी से मिल जाती है और वे साफ बच निकलते है।

शासकीय आदर्श महाविद्यालय झाबुआ में प्रवेश का छठवां चरण हुआ प्रारभ, कॉलेज में पर्याप्त सुविधाएं है उपलब्ध

माही की गूंज, झाबुआ।

उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के निर्देशानुसार शासकीय आदर्श महाविद्यालय झाबुआ में प्रवेश का एक ओर छठवां चरण सीएलसी राउंड 23 से 25 अगस्त तक प्रवेश हेतु चलेगा। जिसमें विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।

महाविद्यालय में 23 से 25 अगस्त तक वे छात्र भी आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने पूर्व में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है या जिन छात्रों को अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ऐसे सभी छात्र-छात्राएं सीएलसी छठवां चरण में भाग लेकर प्रवेश ले सकते है। यह जानकारी संस्था प्राचार्य डॉ एससी जैन के निर्देशानुसार एडमिशन प्रभारी प्रो. संजय खांडेकर ने देते हुए बताया कि महाविद्यालय में बीए, बीकॉम, बीएससी में पर्याप्त रिक्त सीटे है, जो भी छात्र-छात्रा प्रवेश लेना चाहता है, सभी को प्रवेश दिया जाएगा तथा महाविद्यालय में पर्याप्त मात्रा में नियमित स्टॉफ, स्मार्ट लेब, ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब आदि सुविधाएं भी उपलब्ध है।

पर्यूषण महापर्व के दौरान शहर में पधु वध एवं मांस विक्रय केंद्र बंद करवाए जाने को लेकर श्वेतांबर जैन श्री संघ ने सौपा ज्ञापन

भारत सरकार एवं मप्र सरकार के निर्देशों का शहर में हो कड़ाई से पालन

माही की गूंज, झाबुआ।

जैन समाज का पर्वाधिराज पर्यूषण महापर्व आरंभ हो गया है। भगवान महावीर स्वामीजी के संदेष अनुसार यह पर्व अहिंसा के साथ विशेषकर मूक जीवों की हिंसा नहीं करने का संदेश देता है। पर्यूषण महापर्व 24 अगस्त से आरंभ होकर आगामी 31 अगस्त तक चलेंगे। भारत सरकार एवं मप्र सरकार के सख्त निर्देश है कि जैन समाज के इस बड़े त्यौहार के दौरान मांस-विक्रय केंद्र बंद रखने के साथ पशु वध भी ना हो। इसी तारतम्य में श्वेतांबर जैन श्री संघ झाबुआ की ओर से कलेक्टर के नाम एसडीएम श्री गर्ग को ज्ञापन सौंपकर जैन समाज के पर्वाधिराज पर्यूषण महापर्व 24 अगस्त, बुधवार से 31 अगस्त, बुधवार तक शहर में सभी मांस विक्रय बंद की दुकाने बंद करवाए जाने की मांगक रखी गई। इस दौरान किसी भी प्रकार की जीव हिंसा ना हो। जैन समाजजनों की ओर से उक्ताषय का ज्ञापन देने के बाद भी प्रथम दिन बुधवार को शहर में कई ऐसे क्षेत्रों में मांस का विक्रय धडल्ले से होता नजर आया और पशु वध के रूप में इन क्षेत्रों में बकरीयों, मुर्गों की खरीदी-बिक्री भी होती नजर आई। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को पर्यूषण के आठ दिवसीय महापर्व के दौरान भारत सरकार एवं मप्र सरकार के नियमों का कड़ाई से सभी से पालन करवाना अत्यंत आवश्यक है।

93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त

भोपाल। मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल ने प्रदेश के 93 नर्सिंग कॉलेज की शैक्षणिक सत्र 2021-22 की मान्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। इसमें बालाघाट समेत कई जिलों के कॉलेज शामिल हैं। प्रदेश में सालों से चल रहें पुराने नर्सिंग कालेजों की मान्यता निरस्त कर दी गई। जिसके बाद हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में आ गया हैं।

नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी सख्ती बरतते हुए अयोग्य रजिस्ट्रार सुनिता शिजू को निलंबित करने के निर्देश दिए और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का डॉ योगेश शर्मा को व्ववस्था नियुक्त कर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए। तत्कालीन रजिस्ट्रार सुनिता शिजू ने मध्यप्रदेश के 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त कर दी जिसमें कई बड़े ग्रुप शामिल हैं।

दरअसल, वर्ष 2020-21 में मान्यता प्राप्त इन नर्सिंग कॉलेज को अकादमी भवन, छात्रावास, लैब, उपकरण, संबंध अस्पताल के आवश्यक दस्तावेज और वर्तमान समय के फोटो 10 मई 2022 तक उपलब्ध कराने कहा गया था। हालांकि इन कॉलेज ने चाहे गए दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए है।

वहीं जिसके कारण उनकी शैक्षणिक सत्र 2021-22 की मान्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। विभाग ने कहा कि, नर्सिंग सत्र 2021-22 में जिस किसी भी छात्र का एडमिशन सूची में दी गई। कॉलेज में हो वह अपनी कॉलेज से फीस वापस ले सकते हैं।

फर्जी नर्सिंग कॉलेजों से संबंधित मामले को लेकर लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जनहित याचिका लगाई थी। जिस पर बेंच में सुनवाई के दौरान यह बताया गया कि विगत वर्ष खुले हुए 94 नर्सिंग कॉलेजों को इस वर्ष की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा 93 नर्सिंग कॉलेजों को भवन संबंधी नोटिस का जवाब ना देने के कारण मान्यता को निलंबित किया गया है।

इसे लेकर एनएसयूआई मेडिकल विंग के प्रदेश संयोजक रवि परमार ने बताया कि, मध्यप्रदेश लगातार फर्जी नर्सिंग बढ़ रही हैं। एनएसयूआई ने अपना विरोध भी दर्ज किया था जब सुनिता शिजू को रजिस्ट्रार बनाया। लेकिन शासन और प्रशासन ने मलाई खाने के लिए अयोग्य रजिस्ट्रार को बैठा रखा था। रवि ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो कार्यवाई की उसका हम स्वागत करते हैं। और सरकार से मांग करते हैं कि किसी योग्य रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी सौंपी जाए।

जयस की बैठक ग्राम मसूरिया में हुई संपन्न

ग्रामीणों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक कर आगे आने हेतु आव्हान किया

माही की गूंज, झाबुआ।

जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन (जयस) द्वारा झाबुआ विकासखंड के ग्राम मसूरिया में बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता जयस जिलाध्यक्ष विजय डामोर ने की।

इस अवसर पर सदस्यता अभियान के तहत मसूरिया गांव के कई ग्रामीणों ने जयस की सदस्यता ली और समाज के लिए एक होकर काम करने का संकल्प दोहराया। इस दौरान जयस जिलाध्यक्ष श्री डामोर ने उपस्थितजनों को मुख्य रूप से पांचवी अनुसूची पैसा कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही अपने हक-अधिकार जल जंगल और जमीन को सुरक्षित रखने हेतु संयुक्त पहल करने की बात कही। जिलाध्यक्ष श्री डामोर ने आगे कहा कि यदि गांव मजबूत होगा, तो ब्लॉक और जिला भी मजबूत होगा।

इस अवसर पर संगठन के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष माधवसिंह डामोर, झाबुआ ब्लॉक अध्यक्ष बंटी सिंगार, जिला उपाध्यक्ष आयुष ओहरी, रावजी भूरिया, बालू डामोर, राहुल निनामा, रमेश बबेरिया, प्रताप डामोर, पप्पू डामोर, पप्पू वडखिया, कैलाश डामोर, दिलीप डामोर भूरा गणावा आदि सहित ग्राम के अन्य ग्रामीणजन मौजूद रहे।

मोबाइल ऐप से कर्ज लेना पड़ा महंगा, मिट गया परिवार

इंदौर। मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को कहा कि, साइबर पुलिस से विस्तृत जांच कराते हुए पता लगाया जाएगा कि राज्य में मोबाइल ऐप से कर्ज बांटने वाली कंपनियां उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रही हैं या नहीं। मिश्रा ने इंदौर के एक पेशेवर द्वारा अलग-अलग मोबाइल ऐप के कर्ज के जाल में फंसने के चलते अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों को संदिग्ध तौर पर जहर देने और इसके बाद फांसी लगाकर कथित रूप से आत्महत्या करने के सनसनीखेज घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए यह बात कही।

उन्होंने इस घटनाक्रम पर अफसोस जताते हुए यहां संवाददाताओं से कहा,यह बहुत मार्मिक वाक्या है। मैंने इंदौर के पुलिस आयुक्त को इसकी बारीकी से जांच का निर्देश दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि, इस घटनाक्रम के बाद वह राज्य में अलग-अलग कंपनियों द्वारा मोबाइल ऐप के जरिए दिए जाने वाले कर्ज की प्रक्रिया की विस्तृत जांच आवश्यक मानते हैं। उन्होंने कहा,मैं साइबर पुलिस को निर्देश दूंगा कि वह पता करे कि क्या मोबाइल ऐप आधारित कर्ज की प्रक्रिया में कानूनी रूप से कोई आपत्तिजनक पहलू तो नहीं है। अगर ऐसा कोई पहलू मिला, तो हम उचित कदम उठाएंगे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि, इंदौर में एक निजी दूरसंचार कम्पनी में काम करने वाले अमित यादव (35) का शव उनके घर में फांसी के फंदे पर मंगलवार को लटकता मिला, जबकि उनकी पत्नी टीना (30), तीन वर्षीय बेटी याना और एक वर्षीय बेटे दिव्यांश जमीन पर मृत पड़े मिले थे। अधिकारियों ने संदेह जताया कि, मूलतः सागर के रहने वाले यादव ने आत्महत्या से पहले, अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को चाय में जहर दे दिया था। उन्होंने यादव के सुसाइड नोट और मामले की शुरुआती जांच के हवाले से बताया कि, 35 वर्षीय इस पेशेवर ने अलग-अलग मोबाइल ऐप से ऑनलाइन कर्ज ले रखा था और वह इसे चुका नहीं पा रहे थे।

श्रीवास्तव के लिखे गीत को अभिषेक माथुर ने यू-ट्यूब पर गुनगुनाया

बाबा महाकाल उज्जैन को समर्पित इस वीडियो सांग्स को लगातार मिल रहीं लोकप्रियता एवं तेजी से बढ़ रहे दर्शक

माही की गूंज, झाबुआ।

महाकाल की नगरी उज्जैन में विराजित बाबा महाकाल के दर्शन के लिए ना केवल मप्र अपितु देशभर से प्रतिदिन बड़ी तादाद में ऋश्रद्धालुओं का तांता लगता है। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों को प्रेरित करते हुए जिले के पारा निवासी वरिष्ठ समाजसेवी एवं चिकित्सक डॉ. अनिल श्रीवास्तव के भांजे अभिषेक माथुर ने एक सांग्स तैयार किया है। जिसे यू-ट्यूब पर अपलोड करने के बाद लगातार इस सांग्स को लोकप्रियता मिल रहीं है। साथ ही व्यूवर्स भी तेजी से बढ़ रहे है।

जानकारी देते हुए डॉ. अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि वह पत्रकार, चिकित्सक होने के साथ लेखक भी है। उनकी साहित्य में भी काफी रूचि है। उन्होंने भगवान भोलेनाथ पर यह सुंदर गीत तैयार किया, जो उनके भांजे युवा अभिषेक माथुर (सरकार) को काफी पसंद आया और उन्होंने इस गीत को अपनी आवाज में संगीतमय बैक ग्राउंड और बैंक चित्रों के साथ गुनगानते हुए` पिछले दिनों यू-ट्यूब पर अपने बनाए चैनल अभिषेक क्रिएशन पर अपलोड किया। सांग्स के पीछे महाकाल की शाही सवारी का स्लोगन और पीछे नांचते-गाते हजारों भक्त दिखाई दे रहे है। साथ ही इसका टायटल उन्होंने ''भोले थारी उज्जैन नगरी आऊ के ...'' रखा है।

अब तक सैकड़ों लोगों ने देखा

: अभिषेक माथुर ने यू-ट्यूब चैनल पर गुनगुनाया बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन का समधुर संगीतमय गीत।

6 मिनिट और 30 सेकेंड के इस वीडियों को अब तक 1 हजार 400 से अधिक लोग देख चुके है। साथ ही कई दर्शकों ने कमेंट्स और लाईक के माध्यम से इस सांग्स की सराहना की है। अभिषेक माथुर के चेनल के 273 सबक्राईबर्स होकर उनकी यह मंशा है कि यह सांग्स देखकर लोग देवो के देव, आधिपति महादेवजी की महानगरी महाकाल में भोलेनाथजी के दर्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा भक्तजन उज्जैन आए और शाही सवारी में भाग लेने का भी सौभाग्य प्राप्त करे।

समाजसेवी भवानी शंकर राठौर का निधन होने से शोक, सभी ने दी श्रद्धाजंली

माही की गूंज, झकनावदा।

बाल कल्याण समिति झाबुआ के सदस्य, सिंघेश्वर धाम के सक्रिय कार्यकर्ता महेंद्र सिंह राठौड़ एवं भाई अरविंद राठौर के पिताजी मातेश्वरी पेट्रोल पंप के मालिक समाजसेवी भवानी शंकर राठौर का सोमवार को निधन होने से नगर में शोक का माहौल रहा। गत कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नही था। सोमवार को सुबह उनका निधन हो गया, सोमवार को मधुकन्या नदी पर स्थित शमशान घाट पर अंत्येष्टि गायत्री परिवार शक्तिपीठ पेटलावद के जीवन भट्ट व प्रभु भाई लक्षेटा झकनावद ने वैदिक मंत्रोचार के साथ संपन्न करवाई। इस अवसर पर सिंघेश्वर धाम के गादिपति रामेश्वर गिरी महाराज, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष शैलेश दुबे, ग्राम भारती जिला प्रमुख धार से ओम प्रकाश दहिया, रायपुरिया खंड संघचालक धर्मराज पाटीदार, कलसिंह भूरिया, हरिराम पडियार, अजय व्होरा, मग साहब, जितेन्द्र राठौर, हेमेंद्र जोशी, पत्रकार राकेश गेहलोत, अजजा मोर्चे के जिलाध्यक्ष अजमेर भूरिया एवं हजारों की संख्या में गणमान्य नागरिकों ने मधु कन्या नदी के तट पर श्रद्धांजलि दी। लगातार हो रही वर्षा से मौसम भी बहुत खराब था। ऐसे में हजारों लोगों की उपस्थिति व्यक्ति की लोकप्रियता बतलाती है, शक्तिपीठ द्वारा उनके आत्मशांति के लिए हवन में आहुतियां दी गई।

300 बोरी अवैध खाद परिवहन करते गाड़ी व्यापारियों ने पकड़ी, पुलिस में मामला दर्ज

विडंबना : माल भेजने व मंगाने वाले व्यापारियों को नहीं बनाया आरोपी, एफआईआर दर्ज होने तक ड्रायवर भी हुआ फरार

माही की गूंज, थांदला।

20 अगस्त की सुबह थांदला और आसपास के खाद व्यापारियों ने अवैध खाद का परिवहन करने पर एक गाड़ी को तहसीलदार की मौजूदगी में पुलिस थाना परिसर में खड़ा करवा दिया। यह काम कर सभी व्यापारी क्रांतिकारी वाले भाव में आ गए थे। ऐसा इसलिए भी था कि 15 अगस्त से खाद व्यापारियों ने संगठन की बात अनुसार खाद नहीं बेचने का निर्णय लिया था। व्यापारियों की यह अघोषित हड़ताल इसलिए भी थी कि लायसेंसधारी सभी व्यापारी ईमानदारी से शासन के निर्देशानुसार किसानों को सही दाम पर खाद बांटेंगे। परंतु कुछ व्यापारी राजस्थान सहित अन्य राज्यों से अवैध खाद को लाकर ऊंचे दामों में बेच रहे थे, जिसके चलते इन ईमानदार व्यापारियों के व्यापार में बट्टा लग रहा था। इसी बात को लेकर सभी व्यापारी एकजुट थे और अवैध काम करने वाले व्यापारियों पर निगरानी रखकर उन पर कार्यवाही हो, ऐसी मांग कर रहे थे। इसी का नतीजा था कि व्यापारियों ने ही खाद की गाड़ी पकड़ी थी। सुबह तक जो व्यापारी क्रांतिकारी बन रहे थे और कह रहे थे कि अवैध खाद को बेचने और खरीदने वाले व्यापारी पर एफआईआर करवाएंगे। वह शाम तक प्रशासन और खुद के संगठन के आगे बौने साबित हुए। अंततः सिर्फ ड्रायवर के नाम की एफआईआर दर्ज हुई और वह भी पुलिस थाना परिसर से कृषि विभाग के अधिकारियों और खाद-बीज व्यापारियों के सामने से फरार हो गया। आखिर कैसे?

पुलिस रिपोर्ट में सिर्फ ड्रायवर का नाम क्यों?

पुलिस रिपोर्ट और शासकीय पंचनामों में कुशलगढ़ से भेजने वाले खाद व्यापारी का नाम नहीं है। साथ ही इस खाद को कल्याणपुरा में जिस व्यापारी के यहां उतारना था, उस व्यापारी का नाम भी शामिल नहीं है। मतलब साफ है कि व्यापारी और प्रशासन खुद अवैध व्यापार करने वाले लोगों पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं चाहता। सुबह से लेकर शाम तक लगभग 11 घंटों की मशक्कत के बाद थांदला पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 554/22 दर्ज तो हुआ, परंतु सिर्फ फरार वाहन चालक दीपक पिता नाथूलाल नलवाया के नाम पर। तो सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ वाहन चालक ही 300 बोरी अवैध खाद को राजस्थान से खरीद कर कल्याणपुरा तक लेकर जा रहा था? इस घटनाक्रम के दिन ड्रायवर द्वारा खाद भरने वाले कुशलगढ़ के व्यापारी का नाम स्थानीय व्यापारी और मीडिया के समक्ष लिया था। हमारे सूत्रों ने बताया कि इसी दिन थांदला के कुछ व्यापारी कुशलगढ़ गए और उन्होंने खाद भेजने वाले व्यापारी के सामने अपनी पीड़ा जाहिर की। फिर भी पंचनामों में हस्ताक्षर करने वाले और मौके पर मौजूद व्यापारियों ने कुशलगढ़ के उक्त व्यापारी का नाम एफआईआर में दर्ज क्यों नहीं ? मतलब साफ था गुड़ भी खाना था और गुलगुलों से परहेज़ भी दिखाना था।

तहसीलदार के पंचनामे और कृषि अधिकारियों के पंचनामें में अंतर क्यों?

इस कार्यवाही में सबसे पहला पंचनामा तहसीलदार शक्तिसिंह चौहान ने मीडिया और थांदला के व्यापारियों की मौजूदगी में ड्रायवर विशाल के बयान के आधार पर बनाया था। ड्रायवर के बयान के मुताबिक उसने यह माल कुशलगढ़ से 20 अगस्त की सुबह भरा था। यह गाड़ी आरसी के अनुसार किसी ऋषभ एग्रो के नाम से रिजिस्टर्ड है। वर्तमान में इसे किसी कल्याणपुरा के व्यापारी ने खरीदा है। यदि कृषि अधिकारी और व्यापारी संगठन ईमानदारी से काम करते तो निश्चित रूप से इस अवैध कारोबार में लिप्त दोनों पक्ष कानून की जद में आते।

दोपहर से शाम तक झाबुआ और थांदला के कृषि विभाग के अधिकारियों ने पंचनामें बनाए। तब तक तहसीलदार के द्वारा बनाए पंचनामे में शामिल कुशलगढ़ व्यापारी का नाम विभाग द्वारा बनाए पंचनामों में से गायब हो गया। और विभाग वस्तुस्थिति के नाम पर व्यापारी को बचा ले गया। और आश्चर्य तो इस बात का होना चाहिए कि विभाग के पंचनामों में ड्रायवर विशाल के हस्ताक्षर नहीं है और पुलिस रिपोर्ट में वाहन चालक मौके से भाग गया यह लिखा गया।

व्यापारियों में रही चर्चा नहीं तो खुल जाता पूरा खेल

अवैध 300 बोरी श्रीराम यूरिया खाद के मामले की चर्चा नगर के व्यापारियों के बीच रही। उसमें यह बात भी सामने आई कि जिले के एक भाजपा नेता के दबाव में कृषि अधिकारियो ने श्रीराम यूरिया को बेचने ओर खरीदने वाले दोनों व्यापारियों पर एफआईआर नहीं होने दी। साथ जिस आयशर वाहन में अवैध खाद का परिवहन हो रहा था, उस वाहन मालिक को सहआरोपी बनाया जाता। परंतु एक नेता के दबाव के चलते यह सब काम नही हो सका और ड्राइवर पर सारा ठीकरा फोड़ दिया गया। हमेशा छोटी मछली को फंसा कर बड़ी मछली को बचा लिया गया।

व्यापारियों की चर्चा में यह भी सामने आया कि वाहन के चालक के फरार होने के पीछे थांदला के कुछ खाद-बीज व्यापारियों के नाम सामने आने का भय भी था। बताते है कि इसी वाहन से नगर में भी कुछ व्यापारियों के यहां अवैध रूप से खाद आता रहा है। जिसकी जानकारी कृषि विभाग के निरक्षक काग को भी रहती है।

बारिश के चलते खाद को सुरक्षित स्थान पर रखवाया

उर्वरक निरीक्षक उदा काग ने बताया कि पुलिस से अस्थाई सुपुर्दगी लेकर 300 बोरी खाद को मप्र बीज एवं फॉर्म विकास निगम खजूरी के गोदाम में सुरक्षित रखवाया गया है।

वस्तुस्थिति के आधार पर बनाया पंचनामा

कृषि उपसंचालक एसएस रावत से जब हमने पुलिस थाना परिसर में बात की तो उनका कहना है कि मुझे अधिकारियों ने मामले से अवगत करवाया है। वस्तुस्थिति के आधार पर हमने पंचनामा बनाकर पुलिस को दस्तावेज उपलब्ध करवाए हैं। व्यापारियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई इस बात पर वह मुस्कुरा कर बोले, वस्तुस्थिति के आधार पर पंचनामा बनाया है।

एफआईआर दर्ज करवाई है

उर्वरक निरीक्षक उदा काग से बात की तो उनका कहना था कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पंचनामें तैयार किए है। मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवा दी है।

विभाग के प्रतिवेदन पर रिपोर्ट दर्ज

थांदला थाना प्रभारी कौशल्या चौहान ने कहा कि विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर अपराध क्रमांक 554/22 दर्ज किया है। खाद को विभाग को अस्थायी सुपुर्द कर गाड़ी थाना परिसर में खड़ी करवा दी है। मामले में जांच की जा रही है।

राशन की दुकान पर सरकारी अनाज की चोरी का ग्रामीणों ने लगाया आरोप

माही की गूंज, मेघनगर।

मेघनगर से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम डूडका के ग्रामीणों ने राशन की दुकान (उचित मूल्य की दुकान) संचालक जगदीश नायक पर अनाज चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। ग्राम डूडका मे वहां पर स्थित राशन की दुकान पर जहां पर आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो अनाज मिलता है। ग्रामीणों का कहना है कि, जब वह महीने का राशन लेने दुकान पर पहुंचे तो कई अनाज की बोरियों की सील टूटी हुई थी। जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर बोरी में से थोड़ा-थोड़ा अनाज निकाला गया होगा। जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा तुरंत उच्च अधिकारियों को की गई।

उक्त शिकायत व मामले की गंभीरता को देखते हुए मेघनगर तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। समाचार लिखे जाने तक उक्त जांच मौके पर चल रही थी। जिसे देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुकान संचालक पर गाज गिर सकती है।

बता दे कि, इससे पूर्व भी कुछ महीने पहले ग्राम डूडका में इस प्रकार की घटना घटी थी और अनाज चोरी की आए दिन यहां पर घटना घटती है। जिस पर प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

विधानसभा युकां अध्यक्ष मंडलोई ने दिया आवेदन

आज्ञात लोगों पर लगाया गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप

माही की गूंज, अलीराजपुर।

विधानसभा अध्यक्ष युवक कांग्रेस अलीराजपुर, साथ ही नगर में समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। समाज के हर कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वालो में इनका भारी योगदान रहता है तथा समाज में हिन्दू-मुस्लिम एकता के रूप में युवा टीम के साथ बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं।

तरुण मंडलोई, पुलिस थाने से मात्र दो सो मीटर की दूरी पर पुलिस कंट्रोल रूमके पीछे वाली गली में निवास करते। 23 अगस्त को एक बाइक पर सवार 3 अज्ञात शख्स घर के सामने से निकलते हुए तरुण मंडलोई का नाम लेकर बोलते है। उससे पहले वो अपशब्द गालियां दी गई। जान से मारने की धमकी देते हुए तेज गति से फरार हो गये। जब तक मंडलोई घर से बाहर आये उससे पहले ही वह सब मुझे धमकी देकर वहा से निकल जाते है। जिससे उक्त कॉलोनी में भी भय का माहोल व्याप्त है। उक्त घटना को लेकर कार्रवाई के सम्बंध में थाना कोतवाली अलीराजपुर में आवेदन देकर अवगत कराया। साथ ही कॉलोनी में जहा सीसीटीवी लगे हे उसकी जांच कर उक्त आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की मांग की गई। उक्त घटना को लेकर विधायक मुकेश पटेल ने भी अपनी नाराजगी दर्ज करवाई और ठोस कार्रवाई की मांग की।

चौकी प्रभारी ने स्कुली बसों पर भी की चालानी कार्रवाई

कंडम और घटिया बसों में कर रहे बच्चे सफर, जांच हुई तो खुली पोल

माही की गूंज, पेटलावद/सारंगी।

उज्जैन जिले के उन्हेल एवं नागदा के बीच में प्राइवेट स्कूल की तूफान जीप से बच्चों का जो एक्सीडेंट हुआ। उसमें उन्हेल के 4 मासूमों की जान गई। इसी को देखते हुए सारंगी चौकी प्रभारी के सी सीरवी द्वारा पेटलावद के प्राइवेट स्कूलों व प्राइवेट बसों की जांच कर पीसीओ मशीन द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। जिसमें शारदा विद्या मंदिर पेटलावद की बस में काफी अनियमितताएं पाई गई, बस चालक द्वारा सीट बेल्ट भी नहीं लगाया गया, चालक बिना ड्रेस के पाया गया, साथ ही बस में नियमानुसार काफी कमियां पाई गई, चालानी कार्रवाई करते वक्त चौकी प्रभारी के सी सीरवी, एएसआई चौहान, आरक्षक कमल मीणा एवं पुलिस स्टाफ मौजूद था।

कंडम हो रही स्कूल बसे, बड़ी कार्रवाई की दरकार

जब भी कोई बड़ा हादसा या घटना होती है, तो प्रशासन मुस्तेदी के साथ दिखावे की कार्रवाई करता है। लेकिन थोड़े समय मे ही ''ढाक की तीन पात'' वाली स्थित जस के तस हो जाती है। यहां सारंगी में हुई चालानी कार्यवाही के दौरान स्कूल बसों की घटिया व्यवस्था देखने को मिली, मेंटेनेंस के अभाव में बसों की हालत खराब हो गई, प्रोग्रेसिव स्कूल की बस कीं हालत इतनी खराब थी कि, मामूली दुर्घटना में भी बस में बैठे बच्चे बस की सीट से भी गंभीर रूप से घायल हो जाये, ज्यादातर बसे कंडम हो रही है जिनको सुधराने के लिए केवल चालानी कार्रवाई नही बड़ी कार्रवाई की दरकार है।

सड़क की हालत खस्ता, आए दिन हो रहे हादसे

पत्रकारों ने सड़क की दयनीय स्थिति से एसडीएम को करवाया अवगत

माही की गूंज, सारंगी।
संजय उपाध्याय

ग्राम की मुख्य सड़क पर गड्ढों को छिपाने के लिए डाली गई मिट्टी कुछ दिन पहले हुई, मानसून की पहली बारिश में पूरी तरह से बह गई है। हालत यह है कि इन सड़कों के बड़े-बड़े गड्ढे अब दिखाई देने लगे हैं। इनकी वजह से ग्राम वासियों की परेशानी शुरु हो गई हैं। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आवागमन बना रहता है सड़क की हालत तो इतनी खराब है कि डामर की जगह कीचड़ हो रही है। ऐसे में पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। यह सड़क पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती हैं, यही नहीं तीन वर्ष पहले ही मुख्य सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन घटिया निर्माण के चलते डामर बनने के कुछ माह बाद ही रोड उखड़ना शुरु हो गया था। इसके बाद सारंगी नगर के पत्रकार बंधुओ ने समाचार प्रकाशित कर, इस सड़क के बारे में एसडीएम से भी चर्चा की थी। जिस से पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों द्वारा कमियों को छिपाने के लिए गड्ढों को गिट्टी और मिट्टी डलवाकर उसे ढंक दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में बारिश के चलते यह मिट्टी नालियों में बह गई और गड्ढे बाहर आ गए हैं। इन बड़े-बड़े गड्ढों के कारण लोगों का वाहन चलाना भी मुश्किल हो रहा है। गड्ढों में जाकर कई वाहन चालक तो फिसलकर गिर भी गए। इस सड़क पर दिन भर फोर व्हीलर, टू-व्हीलर गाड़ियों का आवागमन बना रहता है। नगर वासियों की मांग है कि, इस सड़क पर डामरीकरण करके लोगों को राहत, जिला प्रशासन एवं पीडब्ल्यूडी विभाग देगा।

पांच घंटे तक चलता रहा एबीवीपी का प्रदर्शन रहा, होस्टल अधीक्षकों पर करवाई के लिए सहायक आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

माही की गूंज, अलीराजपुर।

अखिलभारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) अलीराजपुर द्वारा जिले के समस्त छात्रावासो में अव्यवस्था को लेकर प्रदर्शन कर सहायक आयुक्त जानकी यादव को ज्ञापन सौंपा। जिसमे अभाविप के प्रांत सह मंत्री विनय चौहान ने बताया कि, विगत दिनों में कन्या शिक्षा परिसर जोबट की छात्राए स्कूल समय में स्वयं एसडीएम कार्यालय पहुँचना, एकलव्य उमराली के विद्यार्थी भी वैसे ही अपने व्यय पर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत करना, मंगलवार को बोरी के समीप स्थित ग्राम सेमल खेड़ी में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की कुछ छात्राएं फूड प्वाइजनिंग का शिकार हुई। बावजूद प्रशासन का मौन रहना कही ना कही अधीक्षकों की मनमानी, भ्रष्टाचार व छात्रों के अधिकारो के हनन को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अभी तक उन दोषी अधीक्षकों पर प्रशासन की कोई कार्यवाही नहीं होना प्रशासन का रवैया विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशील नहीं है।

ठीक उसी प्रकार से समस्या को लेकर आए उत्कृष्ट बालक छात्रावास के विद्यार्थियों ने बताया कि, छात्रावास में अनियमितताओं का अंबार लगा है। छात्रावास कक्ष में कहीं पंखे नहीं लगे है, तो कहीं बंद पड़े हुए हैं। छात्रावास में भोजन न समय पर नहीं मिलता न मेनू के अनुसार। शिकायत करने पर छात्रावास में विद्यार्थियों को अधीक्षक द्वारा डरा धमकाया जाता है। छात्रावास में विद्यार्थी को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई जाती है, वह भी अभी तक नहीं दी गई है। छात्रावास में विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक की छात्रवृत्ति मिलती है वह भी कई वर्षो से नहीं मिल रही हैं।छात्रावास में विद्यार्थी को बेड नहीं मिल रहा है, विद्यार्थी एक बेड पर दो सोने पर मजबूर है। ओढ़ने बिछाने का कोई संसाधन नहीं और कई वर्षो से बिस्तर चेंज नहीं हुए। अधिकतर विद्यार्थी घर से संसाधन लेकर आए हुए। छात्रावास में बिजली के बोर्ड सही नहीं है जगह-जगह पर वायर कटे हुए है उसमे छात्रों को पूरी तरह से करंट लगने की संभावना है। अधिकतर शौचालय बंद पड़े हुए हैं कहीं सारे दरवाजे टूटे हुए जिसमें विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

नगर मंत्री केतन चौधरी ने बताया कि, जिन छात्रावासों में अधीक्षक 3 वर्ष से पदस्थ है उनको तुरंत उनकी मूल संस्था में व अन्य छात्रावास में भेजा जाना चाहिए और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को देखते हुए छात्रावासों में सप्ताहिक उपचार के लिए डॉक्टरों की टीम भेजनी चाहिए।

जिला संयोजक निलेश सस्तिया ने बताया कि, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपसे यह मांग करती है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय उमराली के प्राचार्य व अधीक्षक को तुरंत निलंबित करते हुए उन पर विभागीय जांच बैठानी चाहिए व दोषी पाए जाने पर पुलिस कार्यवाही की जानी चाहिए। इसी प्रकार उत्कृष्ट एवं सामान्य बालक छात्रावास के अधीक्षक पर भी जांच दल बिठाकर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई नहीं होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिले भर में आंदोलन करेगी जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। प्रदर्शन में मदन डावर, जेल सिंह मावी, सुरपाल चोंगगढ़, रमेश अवासिया,सुजल सेन, भावेश बृजवासी सहित आदि कार्यकर्ता एवं छात्रावास के विद्यार्थी उपस्थित थे।

संपादकीय

सीधी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता अनिवार्य शर्त

नि:संदेह 21वीं सदी के भारत में वैश्विक मानकों के अनुरूप शिक्षा व प्रशासनिक व्यवस्था में विशेषज्ञों की दरकार है, जो आधी सदी पुरानी औपचारिक पात्रता के मापदंडों से मुक्त हों। लेकिन इसके साथ यह भी जरूरी है कि नई व्यवस्था धनबल, राजनीतिक प्रभाव व अन्य किसी दबाव से प्रभावित न हो। यह जानते हुए कि देश में बड़ी आर्थिक विषमता है और सदियों से वंचित समाज को संविधान ने आगे बढ़ने के लिये विशेष अवसर

दिए हैं। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि, संवैधानिक मापदंडों के अनुरूप कानून सम्मत रोजगार चयन प्रक्रिया में चतुर-चालाक व धनबल के उपासक छिद्र तलाश लेते हैं। पारदर्शिता के मानकों व चयन प्रक्रिया को धता बताकर अकसर चयन परीक्षाओं के पेपर आउट होने से लेकर साक्षात्कार में धांधली के मामले उजागर होते रहते हैं।

बहरहाल, पिछले दिनों दो फैसलों ने सबका ध्यान खींचा। पहला यह कि, देश के विश्वविद्यालयों व उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में विदेशी छात्रों के नामांकन के लिए 25 फीसदी अतिरिक्त सीटें सृजित करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही विदेशी विद्यार्थियों को भारत में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी। पहली बार सुनने में अच्छा लगता है कि, फैसला देश की वैश्विक स्तर पर शैक्षिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। दुर्लभ विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा। लेकिन बिना परीक्षा के प्रवेश देने के नुकसान भी बने रहेंगे। इससे उन धनाढ्य विदेशी परिवारों के बच्चों को डिग्री लेने का सुगम अवसर मिल जाएगा, जो अपने देश में इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं ले पाते। नि:संदेह, इससे डिग्री की गुणवत्ता व शैक्षिक परिदृश्य पर प्रभाव पड़ सकता है। वहीं दूसरे फैसले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की हाल ही में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि, विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षण संस्थान शीघ्र ही स्थापित विशेषज्ञों को एक नई श्रेणी के तहत फैकल्टी मेंबर के रूप में नियुक्त कर सकेंगे जिनके लिए औपचारिक अकादमिक पात्रता एवं प्रकाशन से जुड़ी शर्त अनिवार्य नहीं होगी।

दरअसल, नीति-नियंताओं का मानना है कि पेशेवर प्रोफेसरों वाली इस योजना में इंजीनियरिंग, विज्ञान, मीडिया, साहित्य, उद्यमित्ता, सामाजिक विज्ञान, ललित कला,लोक सेवा व सशस्त्र बल आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस श्रेणी में नियुक्ति पा सकेंगे। विषय में विशेषज्ञता व लंबा अनुभव वरिष्ठ स्तर पर होना अनिवार्य होगा। साथ ही जरूरी है कि दायित्व निभाने का कौशल भी उनके पास हो। ये नियुक्तियां तीन श्रेणियों में होंगी। वहीं 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' की संख्या मंजूर पदों से दस फीसदी से अधिक नहीं होगी। साथ ही वित्त पोषण उद्योग, उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाएगा, वहीं मानद आधार पर तीसरी श्रेणी में नियुक्ति होगी। ये नियुक्तियां विश्वविद्यालय व कालेजों के मंजूर पदों से इतर होंगी। नि:संदेह कई मौलिक प्रतिभाएं विषमताओं अथवा पेशेगत बाध्यताओं के चलते औपचारिक अकादमिक पात्रता हासिल नहीं कर पातीं लेकिन प्रतिभा बेजोड़ होती है। दूसरे हमारे शिक्षण संस्थानों व विश्वविद्यालयों की एक दिक्कत यह भी रही है कि वे शिक्षा व शोध को देश की व्यावहारिक जरूरतों से नहीं जोड़ पाए हैं। ऐसे में विभिन्न क्षेत्रों के व्यावहारिक अनुभव से छात्र लाभान्वित हो सकेंगे।

लेकिन यक्ष प्रश्न है कि, इसके मूल में सत्ता का खेल न हो। केंद्रीय सत्ता द्वारा अपनी विचारधारा व मातृ संस्थाओं के लोगों की उच्च शिक्षण संस्थानों व विश्वविद्यालयों में भर्ती के शार्टकट तरीके अपनाने के आरोप विपक्षी दल लगाते रहे हैं। दरअसल, इससे पहले वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए सरकारी विभागों में संयुक्त सचिव स्तर पर सीधी भर्ती की थी। 2019 में अधिकारियों को पदों पर तैनात भी कर दिया गया। आमतौर पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा व अन्य केंद्रीय सेवा परीक्षा के चयनित अधिकारियों को कैरियर में लंबे अनुभव के बाद ये पद मिलते रहे हैं। हालांकि, बाद में कार्मिक मंत्रालय ने चयन प्रक्रिया का जिम्मा नौकरशाह चुनने वाली यूपीएससी को सौंपा था। दरअसल नीति आयोग का मानना था कि निश्चित अवधि के लिए लेटरल एंट्री के जरिये दक्षता रखने वाले विशेषज्ञों को व्यवस्था में शामिल किया जाये। तब विपक्ष ने आरक्षण नियमों का पालन न करने तथा संस्थाओं के भगवाकरण के प्रयास के आरोप लगाए थे।

क्षमादान और सत्ता - समाज की खामोशी पर प्रश्न

पंद्रह अगस्त के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक होकर लालकिले से नारी-अस्मिता की रक्षा की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में नारी-सम्मान से संबंधित ऐसा कुछ घट रहा था, जिससे मनुष्यता शर्मसार होती है। हां, आज से बीस साल पहले उस दिन भी मनुष्यता शर्मसार हुई थी जब एक गर्भवती महिला के साथ बारह दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार किया था, उसकी तीन वर्ष की बेटी को मार दिया था, और उसके परिवार के सात व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया था। मैं बिल्किस बानो की बात कर रहा हूं। उसके साथ नृशंस व्यवहार करने वालों को अपराधी पाया गया और कानून के अनुसार सज़ा भी दी गयी। जिस 'ऐसा कुछ' घटने की बात से यह बात शुरू हुई है, वह उन सब अपराधियों को क्षमा-दान देने की है। 14 साल की सज़ा भुगतने के बाद उन सब अपराधियों को सरकारी निर्णय के अनुसार जेल से रिहा कर दिया गया। बात यहीं तक सीमित नहीं है। मनुष्यता के शर्मसार होने की घटना और आगे बढ़ती है। वे ग्यारह अपराधी जब जेल से बाहर आये तो उनका स्वागत-अभिनंदन किया गया!

बात यहां खत्म नहीं होती है। इसके आगे जो घटा, या जो नहीं घटा, वह भी कम शर्मसार करने वाली बात नहीं है। होना तो यह चाहिए था कि गुजरात सरकार की इस कार्रवाई पर देश स्वयं को शर्मसार महसूस करता, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। न किसी को शर्म आयी, न किसी को गुस्सा आया! हां, सरकार की इस कार्रवाई पर थोड़ी-बहुत सुगबुगाहट तो हुई, पर यह बात अपने आप में कम शर्मनाक नहीं है कि इस क्षमा-दान और अपराधियों के साथ नायकों जैसा व्यवहार होने का विरोध करने वाली आवाज़ें कब उठीं, और कब कहीं खो गयीं, पता ही नहीं चला!

ऐसा नहीं है कि अपराधियों को पहले कभी क्षमा-दान नहीं मिला। ऐसी व्यवस्था है कि जेल में अपराधियों के व्यवहार, अपराध की गंभीरता आदि को देखकर चौदह साल की सज़ा भुगतने के बाद उन्हें क्षमा-दान मिल सकता है, पर न्यायालय ने यह भी कहा हुआ है कि बलात्कारियों और जघन्य हत्या करने वालों को इस व्यवस्था के अंतर्गत सज़ा में रियायत नहीं मिलनी चाहिए। संभव है, इस मामले में पीड़ित पक्ष फिर से न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाये और शायद अपराधियों को फिर से जेल भेज दिया जाये, पर यहां बात समाज के उस व्यवहार की होनी चाहिए, उस लगभग चुप्पी की होनी चाहिए जो वस्तुतः बहरा कर देने वाली है।

अपराधियों को क्षमा-दान का समाचार जब बिल्किस बानो को मिला तो एक बार फिर वह खतरनाक डर के उसी माहौल से घिर गयी थी जो बाईस साल पहले उसने अपने गांव के पास के खेतों में झेला था। वे सबके सब अपराधी अब फिर से मुक्त थे जिन्हें एक-एक करके उसने अदालत में पहचाना था। मुकदमा चलने के दौरान न जाने कितनी बार बिल्किस बानो और उनके पति को मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां मिली थीं। वे सारी धमकियां उन्हें अब फिर से याद आने लगी थीं। और बलात्कार वाला वह अमानुषिक कृत्य भला कोई कैसे भूल सकता है। फिर भी वह कोशिश कर रही थी उसे भुलाकर एक नयी ज़िंदगी जीने की। अपराधियों के क्षमा-दान ने एक बार फिर वह दृश्य आंखों के सामने ला दिया था। अब फिर बिल्किस का परिवार एक खतरनाक डर में जीने के लिए बाध्य है। कैसे जियेगा, पता नहीं।

यहां हमारे समाज के व्यवहार का सवाल भी उठता है। इस संदर्भ में जो थोड़ी-बहुत सुगबुगाहट हुई उसमें ऐसे स्वरों का उठना भी कम डरावना नहीं है जो एक तरह से अपराधियों के पक्ष में जाते दिखते हैं। बीस साल पहले बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, उसकी भर्त्सना तो सब करते हैं, पर जब इस भर्त्सना के साथ 'लेकिन' लगा दिया जाता है तो कहीं न कहीं नीयत में खोट दिखाई देने लगता है। 'लेकिन' लगाकर कुछ लोगों को यह कहना भी ज़रूरी लगता है कि बिल्किस के साथ जो घटा उसकी पृष्ठभूमि में कहीं गोधरा में रेलगाड़ी में आग लगाये जाने की घटना भी है। गोधरा का यह कांड भी किसी दृष्टि से क्षम्य नहीं कहा जा सकता। रेलगाड़ी के उस डिब्बे में जो कुछ हुआ, वह भी उतना ही जघन्य अपराध था जितना बिल्किस के साथ हुआ अत्याचार। उसके अपराधियों को भी उपयुक्त सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन गोधरा कांड के नाम पर बिल्किस बानो पर हुए अत्याचार की गंभीरता और वीभत्सता को कम समझने की मानसिकता भी किसी अपराध से कम नहीं है। भर्त्सना इस अपराध की भी होनी चाहिए।

होना तो यह चाहिए था कि बिल्किस बानो के परिवार के साथ वहशियाना हरकत करने वालों की माफी और उनके स्वागत-अभिनंदन की भी तीव्रता से भर्त्सना होती। भर्त्सना उस आपराधिक चुप्पी की भी होनी चाहिए जो इस कांड के संदर्भ में पसर रही है।

जिन ग्यारह व्यक्तियों को क्षमा-दान मिला है, वे घोषित अपराधी हैं। न्यायालय ने उन्हें इस अपराध की सज़ा भी दी है। शर्म आनी चाहिए थी उन्हें जिन्होंने अपराधियों का तिलक लगाकर स्वागत किया। यह कृत्य भी अपने आप में मूल अपराध से कम नहीं है। लेकिन इसकी सज़ा शायद अदालत नहीं दे सकती। यह काम जागृत और विवेकशील समाज को करना होता है। सामाजिक स्तर पर यह आवाज़ उठनी ही चाहिए कि ऐसा अपराध करने वालों की, चुप रहकर ग़लत को देखते रहने वालों की भी, सामाजिक स्तर पर भर्त्सना होनी चाहिए।

विश्वनाथ सचदेव

होना तो यह भी चाहिए था कि लालकिले से नारी-शक्ति को रेखांकित करने वाले प्रधानमंत्री इस पूरे कांड का संज्ञान लेते और गुजरात सरकार और देश की इस मामले में चुप्पी पर टिप्पणी करते। यह लालकिले से किये गये ऐलान का अगला तार्किक कदम होता। इसी तार्किकता का तकाज़ा यह भी था कि बिल्किस कांड में क्षमा-दान पर लगे सवालिया निशानों के उत्तरों की तलाश की कोई कोशिश होती भी दिखाई देती। पर, दुर्भाग्य से, ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा।

सवाल किसी बिल्किस के अपराधियों को सज़ा देने का ही नहीं है, सवाल ऐसा वातावरण बनाने का भी है जिसमें ऐसा कोई अपराध करने वालों को डर लगे। किसी बिल्किस को डर-डर कर न जीना पड़े। बिल्किस के अपराधियों ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि उन्हें अपने किये का कोई पछतावा है, और उन अपराधियों का स्वागत-अभिनंदन करने वाले भी यही संकेत दे रहे हैं कि वे उनके अपराधों को क्षम्य मानते हैं। सच कहें तो अपराध ही नहीं मानते! समाज की चुप्पी इस आपराधिक प्रवृत्ति का समर्थन करती दिख रही है। यह सब कुछ डरावना है। यह बदलना चाहिए। कौन बदलेगा? और कैसे?

दवा का काकस

सिद्धार्थ शंकर

भारत में कोरोना वायरस महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान लोगों को घंटों लाइन में लगकर दवा खरीदते देखा गया। संक्रमण फैलने के डर के बावजूद भीड़ के बीच जिस दवा को लेने की होड़ मची थी, वह थी डोलो-650 एमजी की टैबलेट। भारत में तो यह दवा कोरोना वायरस के इलाज का पर्याय बन गई थी। डोलो की लोकप्रियता का आलम यह था कि सोशल मीडिया तक पर इसको लेकर मीम्स भी बन गए। डोलो की निर्माता कंपनी माइक्रो लैब्स को इसकी बिक्री से जबरदस्त फायदा हुआ। हालांकि, 2022 की शुरुआत में कोरोना लहरों के छंटने के बाद जब जांच एजेंसियां फिर से सक्रिय हुईं तो डोलो बनाने वाली कंपनी भी टैक्स में हेराफेरी के मामलों में घिर गई। आरोप लगा है कि माइक्रोलैब्स ने डॉक्टरों को एक हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा के मुफ्त उपहार बांटे, ताकि वे मरीजों को डोलो-650 एमजी दवा लेने की सलाह दें। डोलो की निर्माता कंपनी पर लगे इन आरोपों से मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ खुद भी चौंक गए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने खुद भी यह दवा ली है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर नई याचिका के बाद कंपनी की दिक्कतें बढ़नी तय हैं, जिसका इलाज किसी भी गोली में नहीं है। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इस तरह के मामलों में रिश्वत के लिए डॉक्टरों पर तो केस चलता है, पर दवा कंपनियां बच जाती हैं। याचिका में डॉक्टरों को तोहफे देने वाली दवा कंपनियों की जवाबदेही भी तय किए जाने की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज के लिए यूनिफॉर्म कोड बनाने की जरूरत है। इसके ना होने के चलते मरीजों को ब्रांडेड कंपनियों की

बहुत ज्यादा कीमत वाली दवाई खरीदनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर उनका इलाज करने वाले डॉक्टर महंगे गिफ्ट के लालच में मरीजों को वही दवाई पर्चे पर लिखते हैं। बहरहाल, देश में उस समय दवा की बिक्री को लेकर जिस तरह का माहौल तैयार किया गया, वह सही नहीं है। दवा की एक-एक खुराक के लिए तरस कर मर गए लोगों के साथ यह अन्याय था। माना कि सभी कंपनियों का एक मात्र उद्देश्य कमाई होता है, मगर समय, काल और परिस्थिति भी मायने रखती है। देश में डोलो का कारोबार इसलिए फैला क्योंकि कोरोना के दौर में बढ़ती मांग के बीच पैरासिटामॉल बनाने वाली अधिकतर कंपनियां दवा की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पाईं जबकि डोलो-650 सभी जगह उपलब्ध रही। सीबीडीटी ने इसी कड़ी में आरोप लगाए हैं कि डोलो के निर्माताओं की तरफ से अपनी दवा की जबरदस्त मार्केटिंग और इसका प्रिस्क्रिप्शन तय कराने के लिए डॉक्टरों को 1 हजार करोड़ रुपये के गिफ्ट दिए गए। इसी वजह से डोलो-650 पूरे कोरोनाकाल और इसके बाद भी लोगों के बीच लोकप्रिय रही। भारत में औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) के तहत एक फिक्स फॉर्मूले से बनी आवश्यक दवाओं की कीमतें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तय कर दी जाती हैं। यानी कोई भी कंपनी इस कानून के तहत तय की गईं दवाओं की कीमतों को अपनी तरफ से नहीं बढ़ा सकतीं। जाहिर तौर पर यह एक बड़ी समस्या है। पैरासिटामॉल की 500 मिलीग्राम की टैबलेट की कीमतें औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के तहत सीमित रखी गई हैं। लेकिन इसी दवा की 650 मिलीग्राम की टैबलेट पर डीपीसीओ का नियंत्रण नहीं है। बल्कि दवा कंपनियां 500 एमजी से ऊपर की दवाओं की कीमत खुद ही तय कर सकती हैं। यहीं पर माइक्रोलैब्स जैसी कंपनियों को अपनी डोलो-650 एमजी की कीमत ज्यादा तय करने का मौका मिल गया। जाहिर तौर पर यह एक बड़ी समस्या है। अनुमानों के आधार पर भारत में मौजूदा समय में 80 फीसदी से ज्यादा दवाएं प्राइस कंट्रोल (डीपीसीओ) से बाहर हैं।

प्राण बीज बोने वाले की भी फिक्र करें

लेखक :- कृष्ण प्रताप सिंह

हिन्दी के अपने वक्त के महत्वपूर्ण कवियों में से एक रामकुमार वर्मा ने कभी देश के किसानों को सम्बोधित अपनी 'हे ग्राम देवता! नमस्कार!' शीर्षक कविता में उन्हें तिल-तिल कर प्राण बीज बोने वाले ग्राम देवता बताते और अपनी झोपड़ी झुकाकर राज-द्वार ऊंचे करने का श्रेय देते हुए लिखा था- तुम जन मन के अधिनायक हो तुम हंसो कि फूले-फले देश/ आओ, सिंहासन पर बैठो यह राज्य तुम्हारा है अशेष!

लेकिन आज जब देश आजादी का अमृतकाल मना रहा है, ये अहर्निश कड़ी मेहनत करने वाले जन मन के अधिनायक आजादी के वक्त के विपन्न देश को पहले अपनी विशाल आबादी का पेट भरने में आत्मनिर्भर, फिर खाद्यान्न-निर्यात में सक्षम बनाने के सहज श्रेय से भी वंचित हुए जा रहे हैं, क्योंकि 'न्यू इंडिया' के हसीन सपनों में खोये सत्ताधीशों को इस राष्ट्रीय उपलब्धि के लिए उनके प्रति तनिक भी कृतज्ञता-प्रकाश गवारा नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अर्सा पहले कभी किसी प्रसंग में कहा जरूर था कि किसानों ने कड़ी मेहनत करके देश के खाद्य गोदाम न भरे होते तो सरकार के लिए उक्त अस्सी करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देना कतई संभव न होता, लेकिन अब लगता है कि वह भी उनका जुबानी जमा खर्च भर ही था। उसके फौरन बाद उनकी सरकार ने अमृत महोत्सव वर्ष में ही अनाजों पर कर लगाने का अभूतपूर्व कदम उठाकर सिद्ध कर दिया कि वह किसानों की इस कामना के साथ कतई नहीं है कि देश के खेत इतनी सुनहरी फसलें उगलें कि कहीं कोई भी देशवासी भूखा न सोये और धन-धान्य से परिपूर्ण रहे। इसके उलट उसे वह कार्पोरेटी कहें या कृत्रिम अकाल काम्य, जिसमें गोदामों में भरे अनाजों की कीमत आसमान छूने लगती है और उनकी बिक्री से भरपूर मुनाफा कमाया जाता है। फिर वह इस बात के लिए ही किसानों की शुक्रगुजार क्यों होने वाली कि उन्हीं की मेहनत से कोरोना महामारी की महाविपदा में भी कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तम्भ बना रहा और उसने देश के आर्थिक विकास की नींव को खोखली नहीं होने दिया। भले ही उस दौर में भी उसने महाविपदा को अवसर बनाते हुए कृषि सुधारों के नाम पर उन पर तीन कार्पोरेट परस्त कृषि कानून थोप दिये थे, जिनसे निजात पाने के लिए उन्हें एक साल से ज्यादा लंबा आंदोलन चलाना पड़ा था।

अमृतकाल की सच्ची देशभक्ति का तकाजा तो यही है कि स्वतंत्रता के बाद की सारी पीढ़ियों को बताया जाये कि पचहत्तर साल पहले हम आजाद हुए तो अनाजों की कमी के कारण देशवासियों के पापी पेटों का सवाल कितना विकट था, उसे हल करने के लिए किस तरह विदेशों से आयात पर निर्भर रहना पड़ता था, कैसे कई बार उसकी शर्मिन्दगियां झेलनी पड़ती थीं और किसानों ने हरित क्रांति के रास्ते हालात न बदले होते तो वे शर्मिन्दगियां जानें कब तक हमारा पीछा करती रहतीं।

फिर भी मौजूदा सत्ताधीश पिछली सरकारों के प्रयासों के प्रति उदासीन हैं तो उसके कारण समझना कठिन नहीं है। दरअसल, वे यह सब बताने चले तो उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने गेहूं की विभिन्न उन्नत किस्मों के 18000 टन बीज आयात करने की अनुमति देकर उस हरित क्रांति की नींव मजबूत की थी, जो बाद में देश के गेहूं उत्पादन में बड़ी छलांग का वायस बनी। बाद में इस सफलता को चावल, कपास, गन्ना, फलों एवं सब्जियों आदि के मामले में भी दोहराया गया।

बात निकलेगी तो सत्ताधीशों को यह भी बताना ही पड़ेगा कि इस क्रांति के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास का तंत्र पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों पं. जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के वक्त से ही तैयार किया जा रहा था। बाद में इसके तहत दो मोर्चों पर एक साथ काम किया गया था- किसानों को प्रोत्साहन स्वरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य देना और बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का भंडारण सुनिश्चित कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए कमी वाले इलाकों में वितरित कर लोगों को भूख से बचाना।

कहने की जरूरत नहीं कि अब तक 'सत्तर साल में कुछ न होने का ही प्रचार करते आये वर्तमान सत्ताधीशों के लिए यह सब बताना बेहद अप्रिय होगा। क्योंकि इससे उनके लिए बाद के वर्षों की उद्योगों की खातिर कृषि की बलि लेने वाली उन आर्थिक नीतियों का बचाव करना कठिन हो जायेगा, जिन्हें वे खुद भी पिछले आठ सालों से पालते-पोसते आ रहे हैं और जिनके कारण साल-दर-साल रिकॉर्ड अनाज उत्पादन के बावजूद किसानों की आय ठहर गई या कम होती गई है। इन नीतियों के चलते किसानों की आय दोगुनी करने का चुनावी वादा भी उनके किसी काम नहीं आया है, देश में बड़े पैमाने पर वर्ग असमानताएं पैदा हो गई हैं, सो अलग।

अभी तो सत्ताधीशों का रवैया ऐसा है कि आन्दोलनकारी किसानों से किये गये समझौते के आठ महीनों बाद फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की समस्याओं पर विचार के लिए समिति बनाते हैं तो भी उन्हें अपनी अच्छी नीयत या सदाशयता का विश्वास नहीं दिला पाते। फिर यह कहकर उस समिति की प्रासंगिकता ही खत्म कर देते हैं कि समिति किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर विचार ही नहीं करेगी।

'अखंड भारत' मतलब पूरे देश पर 'एकछत्र राज'

ओमप्रकाश मेहता

देश को अब धीरे-धीरे यह समझ में आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक जमाने से 'अखंड भारत' का नारा लगा रही है, उसका अर्थ और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ केन्द्र के बाद पूरे भारत के राज्यों में भी उसका 'एकछत्र' राज कायम होना है।... और अब उसी 'अखंड भारत' के निर्माण की दिशा में पार्टी काफी सक्रियता बढ़ा दी है और येन-केन-प्रकारेण मौजूदा गैर भाजपाई सरकारों को बदनाम करने-कराने का अभियान शुरू कर दिया गया है। इसका ताजा उदाहरण जम्मू-कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राजनितिक गतिविधियां है। इन राज्यों के अलावा भाजपा की सबसे बड़ी ''आंखों की किरकिरी'' दिल्ली सरकार है, जिस पर राज करने वाली 'आप' पार्टी प्रधानमंत्री जी के गृहराज्य गुजरात के सपने देखने लगी है, इसलिए गुजरात को बचाने के लिए भाजपा वे केन्द्र सरकार जी-जान से जुट गई है।

अब हम यदि गैर भाजपाई शासित राज्यों की चर्चा करें तो सबसे पहले बिहार, जहां कुछ दिनों पहले तक भाजपा सहयोगी दल के रूप में सरकार में थी, किंतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अचानक भाजपा से गठबंधन तोड देने से भाजपा सकते में आ गई है, फिर भाजपा नेतृत्व को यह भी महसूस हुआ कि नीतीश कुमार मोदी जी का विकल्प बनकर 2024 के चुनाव में ताल ठोंककर मैदान में आ सकते है तो वह और अधिक सतर्क हो गई, अब नीतीश कुमार की हर छोटी-बड़ी राजनीतिक गतिविधि पर भाजपा तीखी नजर बनाए हुए है, खासकर उनके और लालू यादव परिवार के मधुर होते सम्बंध पर। नीतीश भी अगले अठारह महीनों का एक-एक पल का पूरा सदुपयोग कर अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने में जी-जान से जुट गए है।

यह तो हुई बिहार की बात। अब यदि हम दिल्ली की आप सरकार के ताजा घटनाक्रमों की चर्चा करें तो वहां तो भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व ने आपके शीर्ष नेतृत्व के चरित्र हनन से अपने अभियान की शुरूआत की है, दिल्ली के मुख्यमंत्री व आप के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल व उनके प्रमुख सहयोगी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को कथित शराब नीति कांड में फंसाकर नए-नए गंभीर आरोप लगाना ही शुरू नहीं किया गया बल्कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया के निवास पर जो सीबीआई को छापा भी डलवा दिया गया और करीब चौदह घंटों तक उनके आवास में खोजबीन की गई, किंतु बताया जा रहा है कि सीबीआई को शराब कांड के कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं मिले, फिर भी सिसौदिया को आशंका है कि अगले दो-चार दिन में उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी उल्लेखनीय है कि इसके पहले आप सरकार के एक और मंत्री सत्येन्द्र जैन की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और वे जेल में ही है। अर्थात् जो सरकार मतपत्रों से नहीं हटाई जा सके, उसे राजनीतिक हथकंड़ों से हटाने के प्रयास किए जा रहे है।

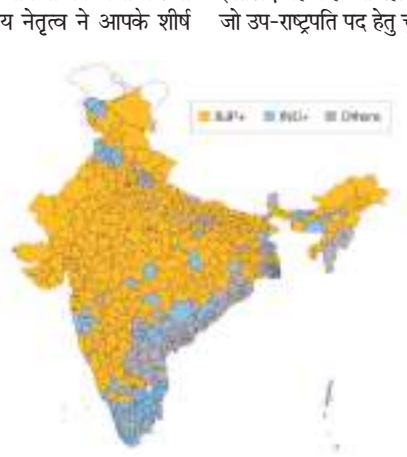

अब बिहार-दिल्ली के बाद यदि पश्चिम बंगाल की चर्चा करें तो वहां जो ममता सरकार के खिलाफ केन्द्र द्वारा किया जा रहा है, वह किसी से भी छुपा नहीं है इसलिए यह कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़े को जो उप-राष्ट्रपति पद हेतु चुना गया, वह उनके ममता विरोधी कदमों का परिणाम है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते श्री धनखड़ ने ममता सरकार के खिलाफ कई प्रशासनिक कदम उठाए। अब ममता का संयुक्त प्रतिपक्ष की नैत्री बनकर भावी प्रधानमंत्री बनने का सुनहरा ख्वाब भाजपा के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। इसी कारण अब ममता केन्द्रीय सरकार व भाजपा के प्रथम निशाने पर है।

अब यदि हम जम्मू-कश्मीर की बात करें, तो उससे यह स्पष्ट होता है कि अपनी राजनीतिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए केन्द्र की भाजपा सरकार संवैधानिक संगठनों का भी दुरूपयोग करने लगी है, हाल ही में जम्मू-कश्मीर के भावी विधानसभा चुनावों में अपनी फतह के लिए भाजपा नेतृत्व ने चुनाव आयोग के माध्यम से गैर कश्मीरी मतदाताओं को भी जम्मू-कश्मीर में मतदान करने की अनुमति दे दी है, जिनकी संख्या करीब पच्चीस लाख है भाजपा की उम्मीद है कि इन पच्चीस लाख वोटों से उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और वहां के स्थानीय दलों पर वह फतह प्राप्त कर वहां अपनी सरकार कायम कर लेगी, अब यह तो भविष्य के गर्भ में है कि भाजपा अपने इन गैर संवैधानिक प्रयासों में कहां तक सफलता प्राप्त कर पाती है?

यदि हम अन्य गैर भाजपाशासित राज्यों की बात करें तो राजस्थान की कांग्रेसी सरकार के खिलाफ जहां आए दिन नए-नए हथकंड़े अपनाए जा रहे है, वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार को जमींदोज करने वाले प्रमुख नेता देवेन्द्र फडनवीस को भाजपा की राष्ट्रीय चुनाव समिति में सदस्यता का ईनाम भी दिया गया, ऐसी ही राजनीतिक चाले देश की मौजूदा अन्य गैर भाजपाई राज्य सरकारों के खिलाफ भी चली जा रही है।

भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व के इन हथकंड़ों से अब यह तो स्पष्ट होने लगा है कि भाजपा 2024 के चुनावों को लेकर आशंकित व भयभीत अवश्य है, उसे अब मोदी जी के नेतृत्व में उतना विश्वास नहीं रहा जितना 2014 व 2019 के चुनावों के वक्त था।

प्रतिपक्ष भी भाजपा के इस भय से पूरी तरह अवगत हो गया है और अपने स्तर पर 2024 में पासा पलटने को आतुर है, किंतु उसके साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह एकजुट है और उसके हर नेता को प्रधानमंत्री पद का रंगीन ख्वाब सताने लगा है, अभी भी समय है यदि प्रतिपक्षी दल व उसके नेता अपने आपसी मतभेद मिटाकर एकजुट हो जाए और अपना निर्विरोध नेतृत्व खोज लें तो 2024 में उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है, ...पर ऐसा हो तब ना....?

श्री पशुपतिनाथ महादेव का कर रही पूर्ण जलाभिषेक शिवना नदी

भारी बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर, आमजन की मुसीबत बड़ी

बाजखेड़ी का तालाब फूट गया है पानी खेतों में घुसने से फसलों को नुकसान हो सकता हैं।

माही की गूंज, मंदसौर। साहिल अगवान

सोमवार से चल रहे वर्षा का दौर मंगलवार को जिले की सभी नदियों में उफान पर ले आया। सभी नदी-नाले उफान पर आने से गांवों में जाने वाले रास्तों को रोक दिया गया। वहीं नाहरगढ़-बिल्लौद मार्ग भी बंद हो गया। इसके अलावा गांधीसागर के जलग्रहण क्षेत्र में बरसात होने से पानी आवक 9 लाख क्यूसेक तक पहुंच गई। और जलस्तर 1306 फीट से 1308 फीट तक पहुंच गया। इससे चलते सभी 19 गेट खोलकर 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे राजस्थान के कोटा सहित म.प्र. के श्योपुर, मुरैना में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया। सावन में 16 अगस्त को ही शिवना नदी ने श्री पशुपतिनाथ महादेव का पूर्ण जलाभिषेक किया था और अब भादौ में भी मंगलवार को शिवना नदी ने सुबह सुबह ही भगवान आशुतोष का पूर्ण जलाभिषेक कर दिया। लगभग 12 घंटे से भी अधिक समय तक शिवना का पानी मंदिर में गर्भगृह में रहा। शिवना नदी का पानी खतरे के निशान 430 मीटर को पार कर 430.320 मीटर तक पहुंच गया था। इसके और बढ़ने की संभावना के चलते ही जयपुर में स्थित केंद्रीय जल आयोग चंबल मंडल के कार्यालय से इस पर निगरानी रखी जा रही थी।

जिले में बारिश के रौद्र रूप से शिवना, तुंबड़, सोमली, रेतम, अंजनी, कंठाली सहित सभी नदियां व नाले उफान पर हैं। सोमवार रात से ही हो रही बारिश के बावजूद कलेक्टर गौतमसिंह ने मंगलवार को सुबह लगभग 8 बजे जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया, जबकि इससे पहले ही बरसते पानी में भी कई बच्चे स्कूल के लिए निकल चुके थे। बाद में सभी वापस लौटे। इंटरनेट मीडिया पर काफी गांधीसागर जलाशय में पानी की आवक 9 लाख क्यूसेक पहुंचने के बाद जलभराव क्षेत्र में स्थित कई गांवों के मुहानों पर पानी पहुंच गया। वहां प्रशासन की टीमे पहुंची और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया और उनके भोजन व अन्य व्यवस्थाएं की।

सोमवार रात से हो रही अनवरत बारिश के चलते मंदसौर की कुछ कालोनियों सहित निचली बस्तियों में भी पानी घुस गया है। अभिनंदन नगर क्षेत्र में स्थित अपना परिसर कालोनी में घरों के अंदर घुटनों तक पानी भर गया है। शनि विहार कालोनी, अशोक नगर,राजीव नगर में भी पानी घुस गया है। रेवास-देवड़ा मार्ग स्थित ऋषियानंद कुटिया के समीप वाली पुलिया का पानी रोड पर बह रहा है। शिवना में पानी की तेज आवक के चलते कालाभाटा डेम के चार गेट 10-10 फ़ीट और एक गेट 5 फ़ीट तक खोला गया। एकाएक बढ़कर 9 लाख 21 हजार 922 क्यूसेक हो गई। जबकि सभी गेटो से मिलाकर बांध से पानी की निकासी 4 लाख 21 हजार 619 क्यूसेक ही हैं। जिला प्रशासन में रविवार रात से ही गांधीसागर बांध क्षेत्र की 5 किमी की परिधि में धारा 144 लगा दी थी। बांध के ऊपर ड्रोन एवं वीडियोग्राफी भी प्रतिबंधित की गई थी। गांधीसागर बांध की स्थिति सहित संपूर्ण जिले में बारिश को लेकर अलर्ट है।

गांधीसागर बांध को लेकर अलर्ट

मंगलवार सुबह 9 बजे से गांधीसागर बांध के सभी 19 गेट खोल दिए गए। वर्तमान जलस्तर 1308.32 फीट तक पहुंच गया है। बांध में पानी की आवक

सोमवार रात से मंगलवार सुबह से लगभग 8 से 9 घंटों में जिले में सबसे ज्यादा 240 मिमी बरसात भावगढ़ क्षेत्र में दर्ज की गई हैं। इसके चलते ही शिवना, सोमली नदी उफान पर आई। सोमली नदी का पानी फतेहगढ़ में भी घुस गया। इसके अलावा सबसे कम 84 मिमी बरसात मल्हारगढ़ में दर्ज की गई।

कलेक्ट्रेट मार्ग पर गड्ढे बन रहे मुसीबत, हो सकता है बड़ा हादसा

माही की गूंज, शाजापुर।

जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट मार्ग बुरी तरह से खराब हो चुकी है। ट्राफिक प्वाइंट से लेकर लालघाटी स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय तक सडक टूटी पडी है। मार्ग पर लालघाटी एमपीईबी कालोनी के सामने से लेकर हिरो होण्डा शोरूम तक नाले का पानी सड़क पर लगातार तेज गति से बह रहा है, जिसके चलते मार्ग पर बड़ेदूबडे गड्ढे हो गए। वहीं उन गड्ढों में पानी भरा रहता है। घाटी होने से चार पहिया व दो पहिया वाहन बहते पानी व गड्ढों से होकर निकल रहे है।

बडे नाले को बंद कर दिया है जिसके चलते पानी तेज गति से सडक पर आ रहा है और बहते पानी व गड्ढों की वजह से कई बार हादसे भी हो चुके हैं। इसके बावजूद न तो एनएचएआई और न ही स्थानीय अधिकारी कोई एक्शन ले रहे। जिससे हाइवे पर कभी कोई कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसी मार्ग पर मंगलवार को दो बाईक सवार दुर्घटनाग्रस्त हो गए। एक बाईक पर कलेक्ट्रेट कार्यालय के दो कर्मचारी भू-अभिलेख शाखा के अकरम व मुन्नालाल साहू पिता हरीराम साहू जो कि मंगलवार शाम ऑफिस से लौट रहे थे कि गड्ढे बचाने में हादसा हो गया।

वही दूसरी बाईक पर दो युवक शुभम शिन्दे पिता आजाद शिन्दे भी दुर्घटनाग्रस्त हो गए। जिन्हे 108 वाहन के ईएमटी प्रेमनारायण दांगी व पायलेट मोहनलाल मोगी ने तुरंत गंभीर घायल अवस्था में जिला अस्पताल उपचार के लिए लेकर पहुँचे। मार्ग पर वाहनों की रफ्तार अधिक होने से गड्ढों के न दिखने से हादसे हो रहे हैं। बरसात के सीजन में तो इस पर पानी जमा हो जाता है। सड़क कई जगह से उखड़ी हुई है। जो किसी गांव की सड़क जैसी हालत बन जाती है।

मंगलनाथ की शाही सवारी में उमड़ा जनसैलाब

माही की गूंज, शाजापुर।

उज्जैन में महाँकाल की शाही सवारी के अगले दिन यानी मंगलवार को शाजापुर में मां राजराजेश्वरी मंदिर परिसर स्थित मंगलनाथ महादेव ने शाही अंदाज में शहर का भ्रमण किया। बैंड-बाजे और झांकियों के साथ निकले देवाधिदेव के दर्शन पाने हजारों लोग सवारी मार्ग पहुंचे। हजारो श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर पूजा-अर्चना की।

सवारी मां राजराजेश्वरी माता मंदिर परिसर स्थित श्री मंगलनाथ महादेव मंदिर से शुरू हुई। भाजपा जिला अध्यक्ष अम्बाराम कराडा, सांसद महेन्द्र सिंह सोंलकी, वरिष्ठ समाजसेवी व वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामवीरसिंह सिकरवार, पूर्व विधायक अरुण भीमावद, नगर पालिका अध्यक्ष प्रेम जैन, पूर्व नपा अध्यक्ष प्रदीप चन्द्रवंशी, भाजयुर्चा जिला अध्यक्ष श्याम टेलर ने बाबा की आरती कर सवारी शुरू की। सवारी रात में सोमवारिया स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। यहां दोनों देवाधिदेव की महाआरती कर प्रसाद बांटी गई। शाही सवारी नगर के मुख्य मार्गों से निकली जहां भक्तों ने उनका पूजन अर्चन किया। महादेव की शाही सवारी में नयनाभिराम झांकियां व टैक्ट्रर-ट्राली पर मलख्म करते युवक-युवतियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रहीं। सवारी देखने पहुंचे लोगों ने झांकी, ताशा पार्टी का आनंद लिया।

कॉन्वेंट स्कूल में शर्मनाक हरकत: टॉयलेट में लगा दिए सीसीटीवी कैमरे, छात्रों ने की शिकायत

शिकायत के बाद हुई कार्यवाही, स्कूल प्रशासन ने हटाये कैमरे

माही की गूंज, रतलाम।

जिले के नामली में स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की शर्मनाक हरकत सामने आई है। स्कूल प्रबंधन ने टॉयलेट (शौचालय) में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। छात्रों ने इसकी शिकायत चाइल्ड लाइन को की। जब टीम के सदस्य स्कूल पहुंचे तो उन्हें छात्रों के दो टॉयलेट में सीसीसीटीवी कैमरे लगे हुए मिले। महिला बाल विकास के चाइल्ड लाइन, हेल्प लाइन 1098 पर 8 अगस्त को नामली नौगांवा स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों द्वारा शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि, उनके स्कूल में शौचालय में कैमरे लगा रखे है। जिससे उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और हम सभी को शर्मिंदगी हो रही है। सूचना के बाद चाइल्ड हेल्प लाइन ने 17 अगस्त को न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के आदेश पर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में चाइल्ड लाइन टीम दिव्या उपाध्याय, लोकेश पाटीदार ने नामली पुलिस थाने से पुलिस आरक्षक कांता चौहान और महेंद्र सिंह चौधरी के साथ पहुंचे। निरीक्षण करने पर पाया गया की स्कूल के दूसरी मंजिल पर कक्षा 9 से 12वीं तक छात्रों के लिए बने दो शौचालय में कैमरे लगे हुए है।

प्राचार्य का अजीब तर्क टीम ने जब स्कूल प्राचार्य से पूछा तो उनका अजीब तर्क रहा। प्राचार्य ने टीम को कहा कि, बालकों द्वारा टॉयलेट में गलत मैसेज लिख देते है, इसलिए कैमरा लगाए गए। उसी के बाद उन्होंने कैमरे हटा दिए। टीम ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर बाल कल्याण समिति को सौंप दी। लेकिन अभी तक स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना जिम्मेदारों की लापरवाही को दर्शाती है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने भी स्कूल में टीम भेज कर जांच कराई तो कैमरे लगे होने की जानकारी सामने आई। जानकारों की मानें तो टॉयलेट में कैमरा लगाना बच्चों के अधिकार के उल्लंघन का मामला बनता है। वहीं इस मामले में स्कूल प्राचार्य सिस्टर निधी को भी उनके मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। प्रेम चौधरी, जिला कॉर्डिनेटर चाइल्ड हेल्प लाइन ने बताया कि, छात्रों की सूचना पर बाल कल्याण समिति के आदेश लेकर स्कूल में टीम ने जाकर देखा तो छात्रों के टॉयलेट में कैमरे पाए गए। पंचनामा बना कर आगे की कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट बालकल्याण समिति को प्रस्तुत कर दी। बालकल्याण समिति के अध्यक्ष सुधीर निगम ने बताया कि, चाइल्ड लाइन टीम के समक्ष प्राचार्य ने गलती स्वीकारी। जिला शिक्षा अधिकारी को भी इस मामले में जांच के लिए कहा। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

केसी शर्मा जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि,बाल कल्याण समिति का पत्र आज ही मिला है। इसके पहले ही सुबह स्कूल में प्राचार्यो की टीम भेज कर जांच की गई है। चाइल्ड लाइन व पुलिसकर्मी के समक्ष कैमरे निकाल लिए गए है। हमारी जांच रिपोर्ट बाल कल्याण समिति व वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाएगी।

17 रुपए में बिकता है गुप्ता रेस्टोरेंट में समोसा-कचोरी

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के साथ ही खाद्य आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई

माही की गूंज, मंदसौर।

शहर में सबसे महंगा 17 रुपए में समोसा-कचोरी बेचने वाले गुप्ता रेंस्टोरेट पर आखिरकार मंगलवार को प्रशासन की वक्र दृष्टि पड़ ही गई। हालांकि यहां आने वाले लोगों से ठीक से व्यवहार नहीं करने आधी सड़क को घेरकर यातायात हमेशा जाम रखने सहित कई शिकायते लगातार होती रही हैं। मंगलवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के साथ ही खाद्य आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम से छापामार कार्रवाई की। यहां से समोसा-कचोरी तलने में उपयोग किया जा रहे तेल का सैंपल लिया हैं। साथ ही कचोरी के मसाले का नमूना भी लिया गया हैं। इसके अलावा भंडार गृह में काफी गंदगी भी मिली हैं। कागजात नहीं बताने पर पांच सिलिंडर भी जब्त किए हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बीएस जामोद ने बताया कि, कार्रवाई करते हुए गुप्ता रेस्टोरेंट एवं कचौरी सेंटर सहकारी बाजार रोड चौराहे का निरीक्षण किया व गुणवत्ता स्तर की जांच के लिए खाद्य पदार्थ के नमूने लिए गए। निरीक्षण के समय गुप्ता समोसा कचौरी के भंडारण कक्ष का निरीक्षण किया गया। उसमें काफी

गंदगी मिली। चूहों की बीट मिली, भंडारण कक्ष में जाले जमे हुए थे। यहां खाद्य पदार्थों का उचित रखरखाव भी नहीं पाया गया। निरीक्षण कर गुप्ता कचौरी से गुणवत्ता स्तर की जांच हेतु कचौरी के तैयार मसालें का नमूना, गर्म कढ़ाई से सोयाबीन तेल का नमूना, कचौरी-समोसे के लिए बनी चटनी व सौंफ का नमूना लिया गया। जब्त नमूनों को अब राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे जा रहे हैं। भंडारण में चूहों की बीट मिली, भंडारण कक्ष में जाले जमे हुए मिले। खाद्य पदार्थों का उचित रख-रखाव भी नहीं पाया गया। इस कारण भंडारण कक्ष को सील किया गया। कार्यवाही के दौरान खाद्य आपूर्ति विभाग को गैस सिलेंडर के दस्तावेज सही नहीं मिले तो 5 गैस सिलिंडर जब्त किए गए।

शमशान घाट पहुंचने के लिए उफनता नाला करना पड़ा पार

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जिले के ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं की पोल खोलकर रख दी है। जिले में आज भी कई गांव ऐसे हैं, जहां बारिश के दौरान लोगों को अंतिम संस्कार करने जैसे नितांत जरूरी कामों में भी जान जोखिम में डालना पड़ती है। ऐसा ही एक नजारा जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर बसे ग्राम अरनिया निजामुद्दीन में देखने को मिला। यहां सोमली नदी में मिलने वाले एक नाले पर पुल नहीं होने की वजह से गांव के बुजुर्ग को समय पर इलाज नहीं मिल पाया। इलाज के अभाव में बुजुर्ग की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीण उफनाते नाले से पानी उतरने का इंतजार करते रहे। आखिरकार लोगों को उफनते नाले के बीच ही मृतक की शव यात्रा श्मशान घाट तक ले जाना पड़ी।

जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में आज दोपहर के वक्त बुजुर्ग प्रभु लाल मालवीय की मौत हो गई थी। अंतिम संस्कार के लिए लोग गांव और श्मशान घाट के बीच बने नाले में आ रही बाढ़ के उतरने का 3 घंटे तक इंतजार करते रहे।लेकिन शाम तक भी नाला नहीं उतरा।

लिहाजा लोगों को मजबूरन 4-4 फीट गहरे पानी में उतर कर मृतक की शव यात्रा को श्मशान घाट तक ले जाना पड़ा। इस मामले में गांव के लोगों ने पहले भी प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने की बात कही है। उधर, मंदसौर तहसीलदार मुकेश सोनी को मामले से अवगत करवाने के बाद उन्होंने गांव का दौरा कर नाले पर पुल बनवाने की बात का आश्वासन दिया है।

मिर्च के नए सीजन से शुरू होंगे तीन नए उद्योग

एक जिला एक उत्पाद में प्रकरण हुए स्वीकृत

माही की गूंज, खरगोन।

एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जिले में मिर्च की फसल का चुनाव किया गया है। जिले के किसानों को मिर्च उद्योग की दिशा में बढ़ावा देने के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा इकाइयां लगाने की कार्यवाही की गई। मिर्च के नए सीजन से जिले में तीन नए मिर्च उद्योग प्रारम्भ होने की स्थिति में है। इसमें जेटवाय के शिवम पटेल और रायबिड़पुरा के अनिल वर्मा व अंजना गुर्जर को पीएमएफएमई के तहत ऋण स्वीकृत किया गया है। ये तीनो ही उद्योग नए सीजन से प्रारम्भ होने की स्थिति में है। शिवम पटेल को योजनांतर्गत 13 लाख 95 हजार, अनिल वर्मा को 34 लाख 74 हजार और अंजना गुर्जर को 25 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ है। स्वीकृत ऋण से मशीनरी खरीदी गई है।

उद्यानिकी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे 11 प्रकरण स्वीकृत हुए है। जिनमे तीन प्रकरणों को बैंक से ऋण स्वीकृत हुआ है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना में 35 प्रतिशत अनुदान पर इकाइयां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सरपंच एवं सचिव आपसी समन्वय से ग्रामीणों के हितार्थ करें कार्य- कलेक्टर

माही की गूंज, बड़वानी।

सरपंच एवं सचिव पंचायती राज की महत्वपूर्ण कढ़ी है। अतः ग्रामों के सरपंच एवं सचिव आपसी समन्वय के साथ ग्रामीणों के हितार्थ कार्य करे। सरकार के द्वारा प्रदेश में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार की यह मंशा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। और हम सब का यह दायित्व है कि शासन की मंशा के अनुसार हम पात्र व्यक्ति को शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं से लाभान्वित करे।

कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा ने बुधवार को शहीद भीमा नायक महाविद्यालय बड़वानी के सभागृह में आयोजित विकासखंड बड़वानी एवं पाटी के सरपंच, उपसरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्यों, सचिव एवं जीआरए को संबोधित करते हुए उक्त बाते कही। इस दौरान उन्होने बताया कि शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हितग्राही के पास उसका समग्र आईडी एवं आधार कार्ड हो। इसलिए समस्त सरपंच एवं सचिव अपने ग्राम में शिविर लगाकर ग्रामीणों के समग्र आईडी, आधार एवं आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से बनाये। जिससे ग्रामीणों को शासकीय योजनाओ का लाभ मिल सके। कार्यशाला के दौरान कलेक्टर श्री वर्मा ने विभिन्न विभागों की हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी देकर, उन योजनाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित करने हेतु प्रेरित भी किया।

गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए संचालित है जिले में मिशन उम्मीद

कार्यशाला के दौरान कलेक्टर श्री वर्मा ने जिले की अनूठी योजना मिशन उम्मीद की जानकारी देते हुए बताया कि, जिले में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए तथा दुर्गम, पहाड़ी, पहुंच विहीन एवं संपर्क विहीन क्षेत्रों से गर्भवती महिलाओं को निकट के प्रसव केन्द्र पर किसी भी प्रेरक द्वारा अपने निजी वाहन/झोली द्वारा संस्थागत प्रसव के लिए मिशन उम्मीद अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत चयनित ग्रामों से निजी वाहन या अन्य साधन से गर्भवती महिला को प्रसव केन्द्र तक लाने पर प्रेरक को न्यूनतम 500 एवं अधिकतम एक हजार रुपये की नगद राशि का भुगतान किया जाता है। प्रेरक गर्भवती महिला के परिवार का सदस्य, पड़ोसी, रिश्तेदार कोई भी व्यक्ति हो सकता है।

एनीमिया को दूर करने के लिए खाये आयरन फोलिक एसिड की गोली

कार्यशाला के दौरान कलेक्टर श्री वर्मा ने बताया कि, सरपंच-सचिव अपने ग्रामों में ग्रामीणों को यह जानकारी दे कि खून की कमी यानि एनीमिया को दूर करने के लिए प्रतिदिन महिला-पुरूष एवं बच्चे आयरन फोलिक एसिड की गोली का सेवन करे, क्योकि इस गोली को खाने से उनके शरीर में खून की कमी नही होगी और उनका हिमोग्लोबिन भी बढ़ेगा। पहले स्वयं खाये और फिर दूसरों को भी आयरन फोलिक एसिड की गोली खाने के लिए प्रेरित करे।

कार्यशाला में कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा, जिला पंचायत सीईओ अनिल कुमार डामोर, जिला पंचायत सदस्य बरमा सोलंकी, जनपद पंचायत पाटी अध्यक्ष थानसिंह सस्ते, जनपद पंचायत पाटी एवं बड़वानी सीईओ सहित बड़ी संख्या में विकासखण्ड बड़वानी एवं पाटी के जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य, सरपंच, उप सरपंच, सचिव, जीआरए उपस्थित थे।

मोबाइल का गलत उपयोग मुसीबत की जड़

माही की गूंज, खरगोन।

प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डलेश्वर के मार्गदर्शन में बुधवार को कृष्णा एकेडमी धरगांव में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव पटेल ने छात्रो को संबोधित करते हुए कहां की मोबाईल कई तरह की बीमारियों का घर है। इसके गलत उपयोग से साइबर क्राइम के केस में आप फंस सकते है। मोबाइल का गलत उपयोग मुसीबत की जाड़ है। उन्होंने बताया कि, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को गलत मेसेज करना, अश्लील फोटो या विडियो शेयर करना विधिक के अनुसार अपराध हैं। ऐसे प्रकरणों में मोबाईल ही महत्वपूर्ण साक्ष्य होता हैं। न्यायाधीश ने मोटर व्हीकल एक्ट के संबंध में से बताया कि लाईसेंस बनवाने की बाद ही वाहन चलाए। बिना लाईसेंस बीमा के वाहन चलाते समय यदि दुर्घटना हो जाती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी वाहन मालिक की होती है। यदि आपने बीमा करवा लिया है तो इस तरह की दुर्घटनाओं में बीमा कंपनी द्वारा प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा प्रदान किया जाता हैं। इसलिए बच्चें अपने अभिभावकों को भी इस बारे में अवगत कराये की अपने वाहनों के लाईसेंस एवं बीमा करवाकर उनका उपयोग करें। विधिक सेवा प्राधिकरण की जानकारी देते हुए बताया के विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। विधिक सेवा समय समय पर स्कूली विद्यार्थियों को कानूनी साक्षरता का ज्ञान देती हैं।

शिविर में छात्र परिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी गयी। शिविर में न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल ने छात्र परिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए कहां कि, यह जो पद मिला है वह आपको दायित्व के रूप में मिला है। पद की गरीमा के अनुरूप पूर्ण निष्ठा एवं ईमादारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। साथ ही अपने विद्यालय के हित में कार्य करते हुए विद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ानी होगी।

इस अवसर पर प्राचार्य अशुवेन्द्रसिंह, संचालक संजय पाटीदार, स्पोर्टस टीचर सौरभ राठौड़, जगदीश वानखेड़े, पैरालीगल वालेंटियर दुर्गेश राजदीप, जोजु एम आर, संदीप पातोडे एवं बड़ी संख्या में स्कूल के छात्र एवं छात्राए उपस्थित रहें।

कलेक्टर की प्रेरणा से युवाओं को सिखा रहे मूर्तिकला

गणेशजी की हाथों से निर्मित मिट्टी की सुंदर प्रतिमाओं का कर रहे निर्माण

माही की गूंज, बड़वानी।

किसी भी कला को सीखकर उसका व्यावसायिक उपयोग करें। गणेश जी की सुंदर प्रतिमाएं आपने बनाई। बड़े पैमाने पर प्रतिमाओं का निर्माण करें और इनकी बिक्री करें। मिट्टी के गणेश जी बनायें, जो पर्यावरण के अनुकूल हों। ये बातें बड़वानी जिले के कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी के स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्षन प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं और अल्पावधि रोजगारोन्मुखी निःशुल्क गणेश प्रतिमा निर्माण कार्यशाला के प्रशिक्षक और प्रशिक्षुओं से कहीं।यह कार्यशाला प्राचार्य डॉ. एनएल गुप्ता के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है।

कार्यकर्ता प्रीति गुलवानिया और मुख्य प्रशिक्षक मूर्तिकार तथा चित्रकार धीरज सगोरे ने कलेक्टर श्री वर्मा को जानकारी देते हुए बताया कि, प्रशिक्षण के दौरान बन रही प्रतिमाओं की बिक्री भी की जा रही है। प्रशिक्षण से जो नये मूर्तिकार तैयार हो रहे हैं, उनके सहयोग से अगले वर्ष अधिक संख्या में प्रतिमाओं का निर्माण करेंगे। इस अवसर पर कन्हैया फूलमाली, वर्षा मुजाल्दे, शैली सोनी, भूमिका कुमरावत ने कार्यशाला में बनी गणेशजी की प्रतिमा कलेक्टर श्री वर्मा को भेंट की।

कॅरियर काउंसलर डॉ. मधुसूदन चैबे ने बताया कि, कलेक्टर श्री वर्मा की प्रेरणा से ही युवाओं को कौशल सिखाने की यह कार्यशाला प्रारंभ की गई है। वे चाहते हैं कि हर युवा सैद्धांतिक अध्ययन के साथ ही हुनरमंद बने और उस हुनर का व्यावसायिक उपयोग करे।

विधिक साक्षरता शिविर में बंदियों को गणेश प्रतिमा बनाने का दिया प्रशिक्षण

माही की गूंज, बड़वानी। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर डीके नागले के निर्देशन एवं जिला विधिक सेवा सचिव नरेन्द्र पटेल के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय मारवाडी महिला मंडल के समन्वय से जिला जेल में बुधवार को विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती पद्मा राजौरे तिवारी ने शिविर को सम्बोधित करते हुए बंदियों से कहा कि आप अपने जेल की अवधि का सदुपयोग कर अपने कौशल को निखारे, जो भविष्य में आपके जीवन यापन में सहयोगी होगा। साथ ही उन्होंने शिविर में विधिक सहायता योजनाओ की जानकारी प्रदान की। इस दौरान मारवाडी समाज की महिलाओं द्वारा बंदियों को मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाने का प्रशिक्षण देकर महिला बंदियों को वस्त्र भी प्रदान किये गये। शिविर में जेल अधीक्षक जेआर मण्डलोई, उप जेलर युवराज मुवेल, पैरालीगल वालेंटियर नीलम पगारे, परसराम गंधारे, मारवाडी महिला मंडल से डॉ. कीर्ति जैन, श्रीमती रजनी उपाध्याय व अन्य महिलाएं एवं जेल कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

कृषि विज्ञान केन्द्र ने गाजरघास उन्मूलन सप्ताह मनाकर ग्रामीणों को किया जागरूक

माही की गूंज, बड़वानी।

कृषि विज्ञान केन्द्र बड़वानी द्वारा विगत सप्ताह को गाजरघास उन्मूलन सप्ताह मनाया गया। इसके अन्तर्गत जिले के पाटी विकासखण्ड के ग्राम देरवालिया में कृषकों को गाजरघास से होने वाले नुकसान के विषय में वैज्ञानिकों द्वारा जानकारी दी गयी एवं जिले के आदान विक्रेताओं हेतु आयोजित 12 सप्ताह के कीटनाशी सर्टिफिकेट कोर्स के दौरान जागरूकता काय्रक्रम आयोजित किया गया।

इस अभियान के संबध में केन्द्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. बड़ोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि, गाजरघास मानव स्वास्थय के साथ-साथ पालतू पशुओं के लिए भी हानिकारक है, भूख लगने पर पशु गलती से इसे खा लेते है इससे इनकी मृत्यु तक हो जाती है, यह घास यत्र-तत्र कहीं भी उग जाती है और इस घास के संपर्क में आने पर मनुष्यों को एलर्जी, खॉसी, बुखार समेत श्वसन संबधी रोग होने की प्रबल संभावना भी रहती है।

केन्द्र के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में केन्द्र के क. वैज्ञानिक डॉ. डीके तिवारी ने भगवंतराव मण्डलोई कृषि महाविद्यालय खंडवा से रॉवे कार्यक्रम अन्तर्गत आई छात्राओं को गाजरघास उन्मुलन हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियॉ व घास की पहचान किस प्रकार की जाय यह जानकारी दी। इसके पश्चात् केन्द्र के प्रक्षेत्र पर उगी गाजरघास को ग्लोब्ज पहन कर सभी छात्राओं व अधिकारी/कर्मचारियों ने उखाड़ कर नष्ट किया। इस अभियान में तकनीकी अधिकारी उदय सिहं अवास्या, क. वैज्ञानिक डॉ. डीके तिवारी, रविन्द्र सिकरवार एवं रंजीत बारा कार्यालय अधीक्षक द्वारा भागीदारी कर सहयोग प्रदान किया।

अवैध रेत उत्खननकर्ताओं की कोशिश हुई नाकामयाब

माही की गूंज, खरगोन।

एक बार फिर अवैध रेत उत्खननकर्ताओं के मुखबिर तंत्र को चकमा देकर रेत खनन पर कार्रवाई करने में खनिज अधिकारी सावन चौहान कामयाब हुए हैं। उत्खननकर्ता द्वारा अधिकारी के जनसुनवाई में होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन खनिज अधिकारी ने मुखबिर तंत्र को चकमा देकर पहले अपने ऑफिस पहुँच गए। वहा से कलेक्टर कार्यालय में योजना के मुताबिक़ पूर्व से ही खड़े वाहन में बैठ कर मुखबिरों को चकमा देकर खनिज अधिकारी निकल गए। अवैध उत्खनन स्थल उमरखली रोड़ कुंदा नदी पर अपनी टीम के साथ पहुँच गए उत्खननकर्ता बेख़ौफ़ होकर ट्रैक्टर में रेत धो रहे थे। तभी खनिज अधिकारी द्वारा दोनों रेत से भरे ट्रैक्टर पकड़े। वहीं एक ट्रेक्टर नदी पार था जो भागने में सफल हुआ लेकिन खनिज विभाग के होमगार्ड जवान राकेश की फूर्ती के कारण उस ट्रैक्टर को भी पकड़ लिया गया। तीनों ट्रेक्टर को दल द्वारा जप्त कर थाना कोतवाली खरगोन की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है।

15 दिन तक चलाया जाएगा नेत्रदान पखवाड़ा, आयोजित होंगे शिविर

माही की गूंज, खरगोन।

राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले में 25 अगस्त से 8 सितंबर तक 37 वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाएगा। नेत्रदान पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य ''आंखो की सुरक्षा'' होगी। बच्चों को पर्याप्त मात्रा में नौ खुराक प्रत्येक छः माह के अंतर से 5 वर्ष की उम्र तक विटामिन-ए की खुराक पिलाए। बच्चों को विटामिन-ए युक्त फल एवं भोजन देना चाहिए जैसे दूध, गाजर, पपीता, हरि सब्जियां भोजन में पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। बच्चों को कम दिखाई देने की शिकायत पर तुरन्त नेत्र चिकित्सक को दिखाना चाहिए। बच्चों को नुकीली चिंजों से नहीं खेलने देना चाहिए। आंख में चोट में नहीं लगना चाहिए, अगर आंख में चोट लगती है तो तुरन्त नेत्ररोग चिकित्सक को दिखाना चाहिए।

नेत्रदान पखवाड़े के अन्तर्गत स्कूलों में छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान बच्चों में विटामिन-ए की कमी से कार्निया में होने वाले अंधेपन से बचाव के लिये स्कुलो में जॉच शिविरो का आयोजन पखवाड़े अंतर्गत किया जाएगा। पखवाडे के अंतर्गत जिले में शासकीय स्कूलो में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के नैत्र परीक्षण के लिए शिविर जिला चिकित्सलय खरगोन एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर आयोजित किये जाएंगे।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले में शासकीय स्कूलो में अध्ययनतर छात्र छात्राओं का नैत्र परीक्षण करने के लिए जिले में जिला स्तर एवं सामुदायिक/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निम्नानुसार स्थानों पर जांच शिविर आयोजित किये जाएंगे। परीक्षण शिविर जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रातः 10 बजे से सांय 4 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण शिविर 25 अगस्त को कोठाखुर्द, बडगॉव एवं सनावद, 26 अगस्त को बेहरामपुर, मण्डलेश्वर, खामखेडा एवं झिरन्या, 27 अगस्त को उमरखली, महेश्वर, बोरावॉ, राईबिडपुरा, झिरन्या, सनावद एवं बडवाह, 29 अगस्त को बिस्टान, महेश्वर, बलकवाडा, डोंगरगॉव एवं बडवाह, 01 सितंबर को करही, मेनगॉव एवं भगवानपुरा, 02 सितंबर को आशापुर, कसरावद, भगवानपुरा, मरदाना एवं कानापुर, 03 सितंबर को चोली, कसरावद एवं भगवानपुरा, 06 सितंबर को साटकुर, ऊन, देवनलिया एवं बेडियां, 07 सितंबर को पाडल्या (महेश्वर ब्लॉक), ऊन, मोहना, चिरिया एवं बलवाडा, 08 सितंबर को काकडदा, बालसमुद, काटकुट एवं बडुद, 09 सितंबर को धरगॉव, सोमाखेडी, बरूड, माण्डवखेडा एवं शिवना, 10 सितंबर को नान्द्रा एवं ढकलगॉव, 12 सितंबर को पिपल्याबुजुर्ग, टेमला, सिरवेल, भीकनगॉव, बागोद एवं खरगोन, 13 सितंबर को बांगरदा एवं खरगोन, 14 सितंबर को बडदिया एवं खरगोन, 15 सितंबर को मुलठान, सेगॉवा, बमनाला एवं जेठवाय, 16 सितंबर को सेगॉवा एवं अंदड, 17 सितंबर को रोडियां, 19 सिंबर को श्रीखंडी, 20 सितंबर को गोगांवां, 21 सितंबर को गोगांवां और केली तथा 22 सितंबर को गोराडिया में नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे।

जो व्यक्ति मरणोपरान्त अपने नेत्रदान करना चाहते है ऐसे व्यक्तियों के नेत्रदान घोषणा पत्र भरे जाएगें, नेत्रदान जिवित व्यक्ति के स्वीकार नहीं किए जाते, नेत्रदान मरणोपरान्त ही स्वीकृत किये जाते है। नेत्रदान करने वाले इच्छुक व्यक्ति के नेत्रदान घोषणा पत्र भरवाये जाने की व्यवस्था प्रत्येक ब्लाक एवं जिला स्तर पर उपलब्ध है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डीएस चौहान ने आम नागरिको से अपील की है कि, नेत्रदान सामाजिक एवं मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत जीवन दान है। नेत्रदान से मृत्यु उपरान्त भी व्यक्ति जीवित रह कर संसार एवं प्रकृति को निहार सकता है, नेत्रदान पखवाड़े के दौरान नेत्रदान महादान के इस अभियान में अपना योगदान करे।

कलेक्टर भवन स्थित पार्क में स्थापित हुई सूर्य नमस्कार की 12 प्रतिमाएं

माही की गूंज, बड़वानी।

नवीन कलेक्टर परिसर के गार्डन में सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राएं प्रस्तुत करती हुई प्रतिमाएं स्थापित की गई है। ये प्रतिमाएं जहां सौंदर्य बढ़ा रही है वही राहगीरों को सूर्य नमस्कार के प्रति सजग भी करेगी। खरगोन शहर में यह प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जहां तक सूर्य नमस्कार को बात है तो यह हमारे शरीर के लचीलापन और स्वास्थ्य के प्रति अतिउत्तम बताई जाती है। सूर्य नमस्कार करने से मांसपेशियों और जोड़ो को मजबूती प्राप्त होती है। सूर्य नमस्कार के कई फायदे हैं। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और नर्वस सिस्टम शांत होता है। साथ ही वजन घटाने में भी मदद करता है।

उद्घाटन के इंतजार में नवीन चिकित्सालय

भवन रंग पुत कर तैयार मगर अंदर अब भी कार्य लगातार जारी

माही की गूंज, आम्बुआ।

प्रदेश शासन की सबको समुचित स्वास्थ्य सुविधा दिलाने हेतु स्वास्थ केंद्रों को नया रूप दिया जा रहा है। कहीं पुराने भवनों को ठीक किया जा रहा है तो कहीं नवीन भवन निर्मित किए जा रहे हैं। ताकि क्षेत्र के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। इसी कड़ी में अलीराजपुर जिले के आम्बुआ कस्बे में भी एक नया भवन तो बन गया, उसकी रंगाई पुताई भी कर दी गई, मगर अंदर अभी कुछ निर्माण कार्य किया जा रहा है। भवन को संपूर्ण बताया जाकर उद्घाटन का इंतजार किया जा रहा है। जवाबदार ठेकेदार तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यहां उपस्थित नहीं होने से जनता नहीं समझ पा रही है कि उन्हें बेहतरीन स्वास्थ लाभ कब मिलेगा...? कब भवन का उद्घाटन होगा...?

जैसा की विदित है कि, आम्बुआ में विगत वर्ष कर्मचारियों के निवास हेतु बने कमरों को तोड़कर एक करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से नवीन अस्पताल का निर्माण ठेकेदार के माध्यम से कराया गया। लगभग 14 कमरों का यह भवन पुराने भवन से बड़ा है। जिसमें चिकित्सकों के कक्ष, मरीजों के लिए कमरे, लेब, मरीजों व उनके परिजनों के बैठने की व्यवस्था तथा अन्य कई सुविधाएं मिलने की उम्मीद की जा रही है। आम्बुआ स्वास्थ्य केंद्र में आसपास के लगभग 2 दर्जन से अधिक ग्रामों के मरीज आम्बुआ स्वास्थ केंद्र पर निर्भर है। अलीराजपुर ब्लॉक, कट्ठीवाड़ा, आजाद नगर तथा उदयगढ़ एवं जोबट ब्लॉक के कई ग्रामीणों का इलाज यहां पर होता है। प्रतिदिन कई माताओं को मातृत्व सुख यानी कि प्रसव कराए जाते हैं तो अन्य मरीजों की संख्या भी सैकड़ों के पार पहुंच जाती है, जिनका इलाज यहां किया जाता है। मगर भर्ती हेतु महिला व पुरुष हेतु एक ही वार्ड है जबकि प्रसूति कक्ष अलग बना हुआ है। नए भवन में सभी कक्षा अलग-अलग बने हुए हैं जिनमें चिकित्सक बैठकर इलाज करेंगे। परंतु यहां अभी जो भी चिकित्सक है वे बाहर से आना-जाना कर रहे हैं। इस कारण शाम 4 बजे से अगले दिन 11 बजे तक मरीज भगवान भरोसे या झोलाछाप चिकित्सकों के भरोसे रहने को मजबूर है।

ग्रामीणों की मांग है कि, नवीन शीघ्र संचालित किया जाए तथा भवन में समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जा कर चिकित्सक स्थाई रूप से रहे ऐसी व्यवस्था हो। पता चला है कि, ठेकेदार भवन पूर्ण बता रहा है। जबकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि, ठेकेदार ने पूर्णतः की न तो सूचना दी है और न ही भवन विभाग को हस्तांतरित किया है। ठेकेदारों एवं अधिकारियों की खींचतान में मरीज बेवजह पीस रहे हैं।

इनका कहना है

डॉ. प्रकाश ढोके सीएमएचओ अलीराजपुर से जब इस बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने बताया, भवन का कार्य अभी कुछ बाकी है। मैंने भवन निर्माणकर्ता को इसकी लिखित जानकारी दी है। अभी विभाग को भवन हस्तांतरित (हैंडोवर) नहीं किया गया है। इस कारण उद्घाटन भी नहीं हो रहा है।

कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई डीएचएस की बैठक

माही की गूंज, अलीराजपुर।

कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति डीएचएस बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने समस्त आंगनवाड़ी वार बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, विटामिन एवं अन्य सप्लीमेंट्री स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। प्रत्येक सीडीपीओ को सेम बच्चों की स्वास्थ्य स्क्रीनिग के निर्देश दिए। गम्भीर अनीमिया बच्चों का चिन्हाकन करते हुए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाए। कोविड टीकाकरण शत प्रतिशत को सुनिश्चित कराए। डीपीटीए टीडी अभियान की प्रगति की समीक्षा की। समय सीमा में शत प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में आरबीएसके की प्रगति की समीक्षा की। स्क्रीनिग की कम प्रगति पर समय सीमा में लक्ष्यों की प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिले के एनआरसी केंद्रों में सेम बच्चों को भर्ती कराने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीआर की समीक्षा की। हाई रिस्क अनीमिया की स्थिति का जायजा लिया। समस्त बीएमओ को नियमित रूप से मनिटरिंग के निर्देश दिए। चार एएनसी की स्थिति की जानकारी लेते हुए जिला स्तरए सीएचसीए डिलीवरी पाइंट पर 4 एएनसी की इंट्री सुनिश्चित कराई जाने के निर्देश दिए। बैठक में जेएसव्हाय की समीक्षा की गई। डिलीवरी पाइंट की प्रगति की समीक्षा की। संस्थागत प्रसव शत प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कायर्क्रम की प्रगति की समीक्षा की जिले के नगरीयए कस्बाई ग्रामीण क्षेत्रों से डेंगू के सैम्पल टेस्ट लिए जाए। बैठक में राष्ट्रीय ष्टिहीनता नियंत्रण कायर्क्रम की प्रगति की समीक्षा की तथा प्रगति सुनिश्चित करने कुष्ठ नियंत्रण कायर्क्रम की जानकारी ली। व्यापक स्तर पर जागरूकता प्रयास, किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक एवं काउंसलिंग की प्रगति की जानकारी ली। राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कायर्क्रम की समीक्षा की।

कलेक्टर श्री सिंह ने मैदानी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से सुनिचित कराया जाए। काम मे कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। बैठक में मुख्य कायर्पालन अधिकारी श्रीमती संस्कृति जैन, सीएमएचओ डॉ. प्रकाश ढोके, डीपीओ आईसीडीएस श्रीमती शिवकली वरवड़े सहित डीटीओए, डीपीओ समस्त बीएमओ, सीडीपीओ, बीपीएमए, बीसीएम सहित अन्य स्टफ व अधिकारीगण उपस्थित थे।

धनकुबेर पर प्रशासन मेहरबान, छापे के बाद भी नहीं किया ससपेंड

जबलपुर। मध्य प्रदेश की ईओडब्ल्यू रेड में बीते दिनों जबलपुर एआरटीओ के यहां करोड़ों रुपए की काली कमाई का भंडाफोड़ हुआ। शुरुआती जांच में ही उसके पास आय से 650 गुना अधिक संपत्ति होने की जानकारी मिली थी। लेकिन संतोष पाल पर राज्य सरकार की मेहरबानी कम नहीं हुई है। राज्य शासन ने अब भी उसे सस्पेंड नहीं किया है।

दरअसल, परिवहन विभाग ने संतोष पाल को पद से हटा दिया है। और उनको संभागीय कार्यालय में अटैच किया गया है। उनकी जगह जितेंदे शर्मा को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। संतोष पॉल 5 वर्ष से जबलपुर में डटे थे। इसके रसूख और प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य सरकार को छापे के बाद पद से हटाने की कार्रवाई में हफ्ते भर का समय लग गया।

वहीं संतोष पॉल ने छापे के बाद मीडिया को इंटरव्यू भी दिया। जिसमें वह शान से कह रहा है कि मुझे ईओडब्ल्यू के छापों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह छापा तो एक प्रक्रिया है। पॉल के घर बीते हफ्ते जब ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची थी तो जांच अधिकारी भी सकते में आ गए थे। करोड़ों रुपए के उसके आलीशान बंगले के भीतर थियेटर से लेकर ऐशोआराम के तमाम साधन मौजूद थे।

इसी दौरान जांच के दौरान ही आरटीओ द्वारा क्रय की गई आई-20 कार, स्कॉर्पियो, पल्सर बाइक और बुलेट के दस्तावेज भी मिले। इस कार्रवाई में मिले दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी द्वारा अर्जित संपति का आकलन करने संबंधी कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।

जांच में पता चला कि आरोपी बंगले के अलावा हजारों वर्ग फुट के करीब आधा दर्जन मकान और कई एकड़ में फैले फॉर्म हॉउस का भी मालिक हैं। साथ ही इसके जबलपुर शहर में दर्जनभर दुकानें भी है। देश के कई बड़े शहरों में भी अतिरिक्त प्रॉपर्टी होने का पता है। जिसके बारे में ईओडब्ल्यू पड़ताल कर रही है।

पुलिस अधिकारी ने पीड़ित महिला को दी गालियां, मामला दर्ज

नीमच।

मध्य प्रदेश सरकार पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली सुधारने की सख्त हिदायत दे रखी हैं। लेकिन उसके बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। ऐसा ही कुछ प्रदेश के नीमच जिले में देखने को मिला है। यहां एक पुलिस अधिकारी का वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। नीमच थाना में तैनात एक सब इंस्पेक्टर महिला को भदी-भदी गालियां दे रहा है। यहां तक की महिला को पुलिसकर्मी जेल भेजने की भी धमकी दे रहा है।

दरअसल, यह वीडियो एक माह पुराना बताया जा रहा है। पीड़ित महिला की खड़ी फसल पर उसके सास ससुर ने कीटनाशक का छिड़काव कर दिया। जिस छिड़काव के बाद उसकी फसल खराब हो गई। जिसकी शिकायत दर्ज कराने महिला पुलिस थाने पहुंची थी। उसकी सुनने के बजाय थाने में मौजूद पुलिसकर्मी ने गाली देनी शुरू कर दी।

वहीं अधिकारी ने महिला को उसके परिजनों की मौजूदगी में पुलिसकर्मियों ने गंदी-गंदी गालियां दीं। विरोध करने पर महिला को सब इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की धमकी दी। जानकारी मिली है कि फरियाद लेकर पहुंची महिला और उसके पति के खिलाफ थाने में धारा 341, 294, 506 के तहत मुकदमा दर्ज होना बताया जा रहा है।

इसे लेकर नीमच एसपी सूरज कुमार वर्मा ने कहा कि, पति-पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगा है। दोनों ने उलटा सब इंस्पेक्टर से अभद्र व्यवहार किया था। इस पूरे मामले की जांच मनासा एसडीओपी को सौंपी गई है। और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विगत वर्ष से टूटी पड़ी नालियों की मरम्मत की उठ रही मांग

माही की गूंज, आम्बुआ।

आम्बुआ कस्बे के गंदे पानी को बाहर निकालने वाली नालियां विगत 2 वर्षों से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। नालियों पर लगी जालिया तथा सीमेंट कंक्रीट उखड़ कर टूट जाने से आवागमन में परेशानी हो रही हो है।

हमारे संवाददाता को आम्बुआ कस्बे के वार्ड क्रमांक 4 के निवासी मगन बघेल, अमान पठान, चांद मोहम्मद तथा वार्ड क्रमांक 3 के निवासी कृष्णकांत जयसवाल, राकेश राठौड़, अमजद खान एवं वार्ड क्रमांक 1 निवासी यूनुस पठान गिरधर खंडेलवाल, वार्ड क्रमांक 3 एवं वार्ड क्रमांक 6 निवासी अनिल माली, मुस्तफा बोहरा, मोहम्मदी बोहरा, बापूसिंह तंवर आदि ने बताया कि, उनके क्षेत्र की नालियों के ऊपर लगी जालियां टूटी हुई है। पोस्ट ऑफिस के पास वार्ड क्रमांक 6 की ओर जाने वाले मार्ग की नाली पर बनी पुलिया (सीमेंट कंक्रीट की छत) टूटी पड़ी है। जिस कारण यहां कभी भी कोई दो पहिया वाहन तथा पैदल चलने वाला नाली में गिर सकता है। नागरिकों ने नालियों की मरम्मत कराने की मांग ग्राम सभा के माध्यम से की है तथा शीघ्र मरम्मत होने की आशा की है।

मामले में रमेश रावत सरपंच आम्बुआ का कहना है कि, मैं अभी निर्वाचित हुआ हूं। पहली ग्राम सभा में नागरिकों ने बताया है तो हम अति शीघ्र ही इस बाबत उचित कार्रवाई कर स्वीकृति प्राप्त कर कार्य कराएंगे।

यातायात पुलिस की 'नेक व्यक्ति योजना' के पुरस्कार में मिलेंगे पांच हजार रुपए नगद

माही की गूंज, आम्बुआ।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों तथा समय पर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने वालों को राज्य शासन की ओर से नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसके प्रचार-प्रसार हेतु जिला यातायात पुलिस विभाग की ओर से आम्बुआ पुलिस विभाग द्वारा इस आशय के ÷पेम्पलेट÷ वितरण किए गए।

आम्बुआ थाना प्रभारी दिलीप सिंह चंदेल ने गूंज प्रतिनिधि को बताया कि, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एक महती योजना प्रारंभ की गई है। जिसके तहत पहले सड़क पर होने वाली वाहन आदि दुर्घटना के समय घायलों की कोई मदद करने को तैयार नहीं होता था। लोग पुलिस की पूछताछ तथा कई बार मदद करने वालों को ही आरोपी मान लिया जाता था तथा न्यायालय के चक्कर काटने के भय से लोग देख कर भी अनजान बन चले जाते थे। जिस कारण घायल सड़क पर ही दम तोड़ देते थे। इसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि, घायलों की मदद करने तथा तत्काल व्यवस्था कर अस्पताल पहुंचाने वाले से उनका पता नहीं पूछा जाएगा। अस्पताल में भी कोई जानकारी नहीं मांगी जाएगी तथा ऐसे मदद करने वालों को अपराधी नहीं माना जाएगा। इस बाबत राज्य शासन द्वारा मदद करने वालों को जिन्होंने एक घंटे के भीतर घायल को अस्पताल पहुंचाया को 5 हजार रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस घोषणा तथा कानूनी परेशानी नहीं होने का भय निकल जाने से लोग मदद को आगे आएंगे तथा घायलों की जान बच सकेगी। उक्त घोषणा का आम जन ने स्वागत किया है। गुड सेमेरिटन (नेक व्यक्ति) के नाम से योजना की घोषणा की गई है।

बलत्कारियों की रिहाई मामले में मुस्लिम यूथ सोशल एसोसिएशन कम्यूनिटी ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

सामूहिक बलात्कारियों की रिहाई वापस ली जाए- मुस्लिम यूथ सोशल असोसिएशन कम्यूनिटी

माही की गूंज, अलीराजपुर।

गुजरात के गोधरा कांड में बिलकिस बानो के साथ हुए सामुहिक बलात्कार के सम्बंध में मुस्लिम यूथ सोशल एसोसिएशन कम्युनिटी ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार अजय पाठक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि, गोधराकांड में बिलकिस बानो के साथ हुए सामूहिक बलात्कार का हम सभी देशवासी घोर निंदा करते है। जिस प्रकार इन सभी आरोपियों को रिहा किया गया है उससे देश की महिलाओं में सुरक्षा को लेकर भय बना हुआ है। ऐसे सामूहिक बलात्कार करने वाले दुष्कर्मी आरोपियों और वेहसी दरिंदो को छुट्टा छोड़ना अगले हादसों को न्योता देना है। इससे ऐसे आरोपियों के हौसले बढ़ते रहेंगे और ऐसे दुष्कर्म होते रहेंगे। जहां एक और बेटी बचाओ और नारी सम्मान का नारा सरकार द्वारा दिया गया है। जो देश भर में वाहवाही लूट रहा है। वहीं ऐसे अपराधियों को रिहा करना नारी का अपमान है। नारी के और बेटियों के बलात्कारियों को खुलल्म खुल्ला सम्मान के साथ रिहा करना बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। इससे सारे नारे वादे खोखले नजर आ रहे हे। आजाद भारत में महिलाओ को आजादी नहीं भय और खौफ में जीने पर मजबूर महिलाए अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रही है। ऐसे आरोपियों और दुशकर्मियों पर पुनः विचार कर उन्हें देश हित में और महिलाओं के हित में फैसला लेकर उचित और सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से निवेदन है की ऐसे आरोपियों को रिहा न कर उन्हें सख्त सजा दें कर देश की बेटियों और महिलाओ को सुरक्षा और जीने की आजादी प्रदान करने का कष्ट करे।

क्या कहा समाजसेवी बाबा ने

ज्ञापन देने के पश्चात समाजसेवी साबिर बाबा ने बताया कि, हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़ी शानो शोकत से कहते है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम भी उस नारे का पुरज़ोर तरीके से समर्थन करते है। लेकिन जब हम इसकी दूसरी ओर देखते हैं तो गुजरात में जो बिलखिस बानो के साथ 11 दरिंदो ने बलात्कार किया ओर उन लोगों को 2004 में गिरफ्तार भी किया गया। मगर अफसोस की बात है कि, 15 अगस्त को अमृत महोत्सव के उपलक्ष में उन लोगों को बड़े सम्मान के साथ रिहा कर दिया गया। ये बड़ी दुःख की बात है। देश को हम किस दिशा में ले जा रहे है।क्या देश में हम ऐसे दरिंदो को इसी तरह से आजाद करते रहेंगे...? आज हम हमारी बहन बेटियो को क्या संदेश देना चाहते हैं...? मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि, ऐसे दरिंदो को फिर से गिरफ्तार किया जाए और क्यों न इन लोगों को फांसी पर लटकाया जाए...! ताकि ऐसा कृत्य कोई भविष्य में न कर सके।

मुस्लिम यूथ सोशल असोसिएशन कम्युनिटी के अध्यक्ष तसद्दुक जिया चंदेरी ने बताया कि, जो गुजरात की बिलखिश बानो के साथ दरिंदगी की गई थी। ऐसे दरिंदो को सम्मानपूर्वक रिहा करना निंदनीय है। चंदेरी ने कहा कि, देश के प्रधानमंत्री अपने झूठे जुमलों से देश को गुमराह कर रहे है। बेटी बचाने का उनका नारा नहीं बल्कि जनता को चेतावनी है, अगर ऐसा नहीं तो देश में दुष्कर्म क्यों बढ़ रहे है और अगर वो महिलाओ के सम्मान में है तो फिर आरोपियों को सजा क्यों नहीं। ऐसे कृत्य करने वाले दरिंदो को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा कृत्य करने की तो दूर उस बारे में सोच भी न सके।

ये रहे मौजूद

ज्ञापन देते समय साबिर बाबा, इलियास गामा, जावेद मकरानी आकिब कुरैशी, इमरान शाह, अमजद मकरानी, जफ़र शैख़ सहित सभी समाजजन मौजूद थे।

बिगड़ैल कुत्ते चैनसिंह की कारस्तानी उसके सहयोगी पर भी गुजरी तो हुई सीएम तक शिकायत

– सीएम हेल्पलाईन पर चैनसिंह के विरूद्व की शिकायत।

माही की गूंज, खवासा/भामल।

एक बिगड़ैल कुत्ता जब लोगों पर भोकता है, या काटता है, तो कुत्ते को पालने वाला मालिक या पड़ोसी जो उस कुत्ते के सहयोगी होते हैं देखकर खुश होते हैं और तो और किसी अन्य व्यक्तियों पर भोंकने या काटने पर इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं कि, बिगड़ैल कुत्ते के भोकने व अन्य को काट देने पर उस कुत्ते को रोटी या हड्डी डालते हैं। लेकिन कहते हैं बिगड़ैल कुत्ता तो बिगड़ैल ही होता है, मौका आने पर वह उसके मालिक या फिर सहयोग करने वाले पड़ोसियों पर भी भौकने व काटने सें नहीं चुकता है। नतीजन जब वह बिगड़ैल कुत्ता खुद के मालिक व पड़ोसियों पर भोकता या काटता है, तब पता चलता है कि, यह बिगड़ैल कुत्ता किसी का नहीं होता है मौका आने पर किसी पर भी भोक सकता है और काट सकता है। तब पड़ोसी व मालिक की आंखें खुलती है कि ऐसे बिगड़ैल कुत्ते का सहयोग करना व रोटी के साथ हड्डी डालना कहां तक जायज था...?

कुछ ऐसा ही एक मामला भामल की आदिम जाति सहकारी संस्था में देखने को मिला। जिस पर क्षेत्र के लोग मामले में चुटकी ले-लेकर चर्चा कर रहे हैं कि, जब लोगों पर चैनसिंह भोकता था, या काटता था तो अच्छा लगता था और पीड़ितों को सहयोग करने के बजाए भ्रष्ट कुत्ता चैनसिंह का सहयोग कर हर बार बचाया जाता था। परंतु इनके पालतु कुत्ते चैनसिंह ने जब पालने वाले को भोका तो पता चला कि, चैनसिंह रुपी बिगड़ैल कुत्ता कितना खतरनाक है, जो किसी पर भी वक्त आने पर भोकने व काटने में कोई चूक नहीं करता।

भामल आदिम जाति सहकारी संस्था पर कई समय से अपना अधिकार जमाकर प्रबंधक के रूप में पदस्थ होकर कई नए-नए अनियमितताओं व भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाला चैनसिंह रिटायरमेंट का समय नजदीक आने पर भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। पिछले ही वर्ष की बात करें, तो एक मामला सामने आया था जिसमें सर्वप्रथम माही की गूंज ने खुलासा किया था कि, किस तरह से चैनसिंह अपने पद का दुरुपयोग कर अपने ही निजी वाहन में खाद्यान्न के साथ खाली बारदान की हेरा-फेरी कर रहा था। जिसके बाद मामले में चैनसिंह को प्रबंधक पद से हटाकर जांच के नाम पर ढकोसला कर जवाबदारों ने पुनः पूर्व की तरह भ्रष्टाचार में क्लीन चिट की तर्ज पर प्रबंधक के पद पर विराजित कर दिया।

उक्त मामले में भी चैनसिंह को हमेशा की तरह राजनीतिक स्तर से सहयोग करने वाले कमलसिंह चावड़ा ने अपने प्रभाव के साथ स्थानीय नेता से लेकर सांसद तक बात कर झूठे गवाह एवं बयानों के आधार पर उक्त मामले को भी रफा-दफा कर प्रबंधक के पद पर पुनः चैनसिंह को पदस्थ करवा दिया। वहीं चैनसिंह की कारस्तानियों को लेकर एक बार फिर मामला तब चर्चा में आया, जब चैनसिंह को उसकी भ्रष्टाचारी कारस्तानियों पर हर बार पर्दा डालने हेतु चैनसिंह के साथ खड़े रहने वाले भाजपा खवासा मंडल के महामंत्री कमलसिंह चावड़ा को रासायनिक खाद का परमिट बनाने के बाद खाद नहीं देने एवं एक बिगड़ैल कुत्ते की तर्ज पर जब चैनसिंह ने अपने मुंह जुबानी कुत्ताई गिरी भोक-भोक कर कमलसिंह के साथ की गई। मामला कुछ यू चर्चा में सामना आया कि, 13 अगस्त को कमलसिंह चावड़ा के पिता भुवानसिंह चावड़ा के नाम से 10 बोरी यूरिया, 22 बोरी डीएपी, 10 बोरी पोटास कुल 42 बोरी रासायनिक खाद का परमिट 49 हजार 3 सौ 65 रुपए का केसीसी के रूप में बनाया। 13 अगस्त को कार्यालय समय बंद होने के कुछ समय पहले ही परमिट बनाया था। जिसके कारण खाद कमलसिंह चावड़ा नहीं ले पाया। जिसके बाद 2 दिन आकास्मिक कोई कार्य आ जाने से खाद लेने हेतु कमलसिंह या उसके पिता संस्था में नहीं जा पाए। नतीजन 2 दिन बाद खाद की उपलब्धता जानने व फोन पर परमिट का खाद लेने हेतु संस्था में आने की बात कमलसिंह ने चैनसिंह से कहीं, तो चैनसिंह बिगड़ैल ही नहीं वरन हड़किए कुत्ते की तरह कमलसिंह पर फोन पर ही भोकने लगा और कमलसिंह को कहा कि, जिस दिन परमिट बनाया उस दिन खाद क्यों नहीं ले गए, अब तुम्हें खाद नहीं मिलेगा। जिस पर कमलसिंह ने कहां खाद नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं परमिट निरस्त कर केसीसी खाते में नामे मत चढ़ाना। जिसके बाद चैनसिंह ने कमलसिंह को भोंकते हुए कहां परमिट भी कैंसल नहीं होगा, न ही केसीसी रिकॉर्ड में चढ़ी खाद की एंट्री हटेगी और न ही आपको खाद मिलेगा, आपको जो करना हो कर ले, और चिल्लाते हुए फोन काट दिया।

– कमलसिंह के पिता के नाम से बनाया परमिट पर खाद देने सें किया इंनकार।

जिसके बाद कमलसिंह चावड़ा हरकत में आया और हर अनियमितताओं पर चैनसिंह का सहयोग किए जाने पर स्वंय पछतावा करने लगा और उक्त मामले की शिकायत क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक नेता से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक कर दी। वही चैनसिंह की भ्रष्टाचार रूपी कुत्ताईगिरी स्थानीय लोगों के साथ पत्रकारों को भी कमलसिंह बताकर कह रहा हैं कि, इस चैनसिंह रूपी कुत्ते को हमने कई बार बचाया है और आज यह कुत्ता हम पर ही भोक कर, हमें काटने का प्रयास कर रहा है, इसका हर्जाना तो अब चैनसिंह को भुगतना ही पड़ेगा।

अब देखना यह है कि, कमलसिंह अपनी शिकायतों पर कहां तक अडिंग रहता हैं या चैनसिंह की भ्रष्टाचार के साथ सांठ-गांठ वाली राजनीतिक में सफल होकर चैनसिंह इस बार कमलसिंह को भी शांत करने में सफल होंगा...?

पेटलावद को झाबुआ से जोड़ने वाले मार्ग की हालत खस्ता

न्यायलीन मजिस्ट्रेट सहित सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का होता है रोज आना-जाना

माही की गूंज, पेटलावद।

नगर धीरे-धीरे बड़े शहर के रूप में चारो तरफ फेल रहा है और बढ़ती आबादी के साथ नगर में वाहनों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। वही नगरवासियों में आवश्यक सुविधाएं भी बढ़ाने की मांग उठती रहती हैं। विभिन्न सुविधाओं के साथ ही नगर में रोड़ की खराब दुर्दशा को लेकर नगरवासियों की लगातार प्रतिक्रियाये सामने आ रही है।

गांधी चौक से लेकर हनुमानगढ़ और माही कालोनी रोड की हालत खस्ता

पेटलावद से झाबुआ को जोड़ने वाला मार्ग गांधी चौक से लेकर माही कॉलोनी रोड और आबकारी के सामने हनुमानगढ़ रोड को लेकर नगरवासी परेशान हो रहे है। सड़क बड़े- बड़े गड्ढो में तब्दील हो चुकी है और पूरे रोड पर बरसाती पानी और कीचड़ की वजह से लोगो का निकलना मुश्किल हो गया है। कई वाहन कीचड़ में फस जाते है और हादसों का भी अंदेशा बढ़ गया है।

अधिकारीयो, जजो ओर जनप्रतिनिधियों के है आवास और कार्यालय

उल्लेखनीय है कि, इसी मार्ग पर निजी स्कूल के अलावा सभी अधिकारी व विधायक का आवास है। वह शहर का सबसे बड़ा स्कूल इसी रोड पर है, जज साहब का बंगला भी इसी रोड पर है और एक कॉलोनी इसी रोड पर है वही एसडीओपी कार्यालय, बिजली विभाग का कार्यालय भी इसी मार्ग पर मौजूद है। और इंटीरियल का रोड और झाबुआ के लिए शॉर्टकट रोड उसके बावजूद भी रोड की हालत इतनी खराब है कि, वाहन चालकों और पैदल चलने वाले लोगो को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्राथमिक वर्ग प्रारम्भ

माही की गूंज, थांदला।

स्थानीय मेट्रो गार्डन परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्राथमिक वर्ग का शुभारंभ दिनांक 23 अगस्त को हुआ वर्ग दिनांक 31 अगस्त तक अष्ट दिवस दो वर्गों में आयोजित हो रहा है द्य एक वर्ग 40 वर्ष से अधिक आयु वाले स्वयंसेवकों का विशेष रतलाम विभाग का वर्ग और एक वर्ग झाबुआ जिले का दोनों वर्गों में चयनित स्वयंसेवकों का वर्ग चल रहा है द्य जिसमे प्रातः 4-30 बजे से जागरण के साथ रात्रि 10-30 बजे तक दिनचर्या में अपने स्वअनुशासन का पालन करते हुवे शारीरिक ,बौद्धिक और व्यवहार कुशलता में वृद्धि का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। दोनों वर्गों में 144 स्वयंसेवक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें हैं। वर्ग में प्रांत ,विभाग के अधिकारियों का प्रबोधन,मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है।

एलोपैथिक पद्धति से इलाज करते हुए रंगे हाथों पकड़ाया झोलाछाप बंगाली

माही की गूंज, बनी। ऋषभ गुप्ता

कलेक्टर सोमेश मिश्रा के आदेश का परिपालन करते हुए पेटलावद ब्लॉक की स्वास्थ टीम के द्वारा झोलाछाप बंगालियों के खिलाफ धरपकड़ की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम में डॉक्टर गुंजन भाभर, नोडल चिकित्सा अधिकारी डॉ. जयेश स्वर्णकार, सीएचओ रामनगर अमृतलाल राठौड़, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुरिया राजू वैष्णव, एमएनए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटलावद और रायपुरिया पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। उक्त टीम द्वारा जब झोलाछाप बंगाली डॉ. मिलन विश्वास बनी के यहां कार्रवाई की गई तब झोलाछाप बंगाली एलोपैथिक पद्धति से इलाज करते हुए पाया गया। जिसके खिलाफ स्वास्थ विभाग की टीम के द्वारा मौका पंचनामा बनाकर एलोपैथिक दवाइयां जप्त की व हिरासत में लेकर रायपुरिया पुलिस थाने ले जाया गया। रायपुरिया पुलिस द्वारा झोलाछाप मिलन विश्वास के खिलाफ मध्य प्रदेश राजकीय आयुर्विज्ञान परिषद एक्ट 1956, 1958 की धारा 24 एवं मध्य प्रदेश उपचार्य ग्रह तथा संबंधी अधिनियम 1973 संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 3 का पाए जाने पर कायमी पंजीबद्ध कर हाजिर जमानत पर रिहा कर दिया। बंगालियों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह जिस समय आए थे तब इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। मगर आज इनकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो इनके पास भोग विलास के सारे साधन मौजूद है। आज की तारीख में इनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके द्वारा भोले-भाले आदिवासी के साथ कितनी लूट की गई है।

स्वास्थ विभाग को मारते ताना

विशेष सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि, उक्त बंगाली फर्जी डॉक्टर ने कहा कि, 'हमारा क्या बिगाड़ लिया, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, हमारी सेटिंग ऊपर तक है, हम गांधी छाप देते हैं, हमें इलाज करने से कोई नहीं रोक सकता और आज भी हम खुलेआम इलाज कर रहे हैं और करते रहे।'

बिना जांच-पड़ताल के बना डाले राशन कार्ड

जिस समय इन झोलाछाप बंगालियों ने गांव बनी में पैर रखे उस समय इनके पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं था। मगर उस समय के पंचायत के कार्यकाल ने बिना आईडी प्रूफ लिए इनका राशन कार्ड बना दिया और नामावली में नाम भी दर्ज हो गया। उस समय के पंचायत प्रशासन के द्वारा बिना आईडी प्रूफ के कूपन बनाना क्या उचित था...? जिसकी भी जांच की जानी चाहिए।

पूर्व में भी हो चुकी कार्रवाई

फर्जी झोलाछाप बंगालियों ने वैसे तो गांव में पिछले कई वर्षों से अपने पैर जमा रखे हैं। मगर स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कुछ वर्ष पूर्व मिलन विश्वास को एलोपैथिक पद्धति से इलाज करते हो पकड़ा था और पुलिस द्वारा इन्हें जेल भेज दिया गया था। उस समय इन झोलाछाप बंगालियों ने लिखित में दिया था कि आज के बाद हम एलोपैथिक पद्धति से इलाज नहीं करेंगे। मगर इन फर्जी बंगालियों द्वारा कोर्ट को भी गुमराह किया गया और कानून का मजाक उड़ाते हुए रोज खुलेआम भोले-भाले आदिवासियों का इलाज करते हुए शोषण किया जा रहा है।

छापेमारी के 13 दिन बाद थांदला के 5 अवैध चिकित्सकों पर दर्ज हुआ मामला

माही की गूंज, थांदला।

5 अगस्त को थांदला नगर के कई अवैध चिकित्सकों पर नायाब तहसीलदार अनिल बघेल और बीएमओ डॉ. अनिल राठौर के नेतृत्व में टीम ने छापामार कार्यवाही की थी। इस कार्यवाही में टीम ने तात्कालिक रूप से अवैध चिकित्सकों से प्राप्त दवाइयों को लेकर पंचनामा बनाया था। यहां पर आश्चर्य की बात तो यह है कि न तो किसी भी दुकान को सील किया गया न ही मीडिया को कोई जानकारी दी गई। मीडिया ने बीएमओ डॉ. अनिल राठौड़ से संपर्क करना चाहा तो उन्होंने कइयों के फोन नहीं उठाए तो कुछेक को प्रेसनोट बना कर भेज रहे है का लॉलीपॉप थमा दिया। जब हमने कार्यवाही में शामिल नायाब तहसीलदार अनिल बघेल से संपर्क साधा तो उन्होंने कहा कि जो भी जानकारी है, वह बीएमओ देंगे। इस बीच न तो मीडिया को उन चिकित्सकों की एकदम सटीक संख्या की जानकारी थी, जिन पर कार्यवाही की गई है। और न हीं किन लोगों पर मामला दर्ज होगा इसकी। फिर अचानक केवल 5 लोगों पर एफआईआर की खबर बाहर आई। इसका मतलब या तो बाकी के चिकित्सक वैध डिग्रीधारी होंगे या वह इस कार्यवाही से बाहर कर दिए गए होंगे। सवाल कई है क्योंकि कार्यवाही को लेकर कोई आधिकारिक वक्तव्य प्रशासन की और से मीडिया को नहीं दिया गया। जिन अवैध चिकित्सकों पर कार्यवाही की गई है, वह भी एफआईआर होने के बाद भी खुलेआम अपनी दुकानें खोलकर इलाज़ कर रहे हैं।मतलब साफ है कि उन्हें भी प्रशासन यह समझाने में सफल रहा होगा कि जो कुछ कर रहें है दिखावे के लिए ही कर रहें है। यहां यह बात भी गौर करने वाली है कि 22 तारीख को राणापुर में भी इसी तरह की कार्यवाही हुई और उसी दिन 2 अवैध चिकित्सकों पर एफआईआर दर्ज हो गई।

झोलाछाप डॉक्टरों के भरोसे आमजनों का स्वास्थ्य

प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सालाना स्वास्थ्य विभाग को करोड़ों रुपयों का बजट देती है। जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त सुविधाओं का दावा भी शासन व प्रशासन करता है। बावजूद इसके मरीजों की समस्याओं की हजारों शिकायतें प्रशासन तक पहुँच रही है। आखिर क्यों? स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता कहे या जिम्मदारों की हठधर्मिता जिसके चलते मरीजों को क्षेत्र के झोलाछाप अवैध डॉक्टरों से इलाज को मजबूर होना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों के हालातों की बात करें तो डॉक्टर ओपीडी के समय ही नहीं मिलते। संसाधनों के अभाव के स्थ ही अस्पतालों से दवाइयां मिलने तक के दावे झूठे साबित हो रहे है। जिसके कारण मरीजों को झोलाछापों से ईलाज करवाना पड़ता है। प्रशासन भी कागदी खानापूर्ति के लिए यदाकदा झोलाछाप अवैध डॉक्टरों पर कारवाई करता दिखता है। जिसकी बानगी हमने 5 अगस्त को हुई कार्यवाही में देखी है। जबकि म.प्र.मेडिकल कांउसिल भोपाल के पत्र क्रमांक स्वास्थ्य/परिपत्र-4/6/114-1256 भोपाल दिनांक 25.03.2006 के माध्यम से अवैध चिकित्सा व्यवसाय पर सतत कारवाई के आदेश है।

थांदला अंचल की स्वास्थ्य सुविधाएं हुई बीमार

पांच अवैध चिकित्सकों पर एफआईआर

स्थानीय प्रशासन की टीम ने 5.8.2022 को नगर के अवैध चिकित्सको के यहां छापेमारी की कारवाई को अंजाम दिया था जिसके लंबे समय बाद दिनांक 18.8.2022 को पाँच अवैध चिकित्सकों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई।जिसमें आशीर्वाद क्लिनिक के मोहनलाल निनामा, कृष्णा क्लिनिक के सागर कुमार मित्रा, ओम साईं मेडिकल स्टोर के नीलेश कुमार बांगड़िया, आयुष क्लिनिक के सोहन कटारा, न्यू साईं क्लिनिक के मुकेश नायक पर मध्यप्रदेश राज्य आर्युविज्ञान परिषद एक्ट 1956 व 1958 की धारा 24 सहित म.प्र.उपचार्य ग्रह तथा रजोपचार्य सम्बन्धी स्थापनाएँ पंजीकरण की धारा 3 के तहत कारवाई की गई। यह कार्यवाही थांदला पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 548 से 552 तक पंजीबद्ध है।

थांदला का सिविल अस्पताल बीमार

स्थानीय सरकारी अस्पताल जिसे नई बिल्डिंग के साथ सिविल अस्पताल का नाम दिया गया है। जिसके आगे भाजपा के पितृ पुरूष पूर्व प्रधानमंत्री स्व.अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा भी स्थापित है। जिस पर माल्यार्पण के लिए चुने हुए भाजपा के जनप्रतिनिधि सहित जिले के पदाधिकारियों का आना जाना लगा रहता है।तो कभी-कभार सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को फल-बिस्किट वितरण कर फोटो भी खिंचवाए जाते रहे है। यही अस्पताल चिकित्सकों की कमी, संसाधनों की किल्लत, मौजूदा चिकित्सकों का ओपीडी के समय मौजूद नहीं रहना और बीएमओ का स्टॉफ के साथ तालमेल नहीं होने से यह सिविल अस्पताल बीमारी की हालत में है। जबकि यह अस्पताल 67 पंचायतों में आने वाला थांदला क्षेत्र का बड़ा अस्पताल है।

मौसमी बीमारियों के चलते झोलाछापों के यहां रहती है भीड़

झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा बिना पंजीयन के एलोपैथी चिकित्सा व्यवसाय ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि बिना ड्रग लाइसेंस के दवाओं का भंडारण व विक्रय भी अवैध रूप से किया जा रहा है। दुकानों के भीतर कार्टून में दवाओं का अवैध तरीके से भंडारण रहता है। इन दिनों मौसमी बीमारी ने दस्तक दी है, जिसके बाद झोलाछाप डॉक्टरों की दुकानें मरीजों के लिए फिर सजने लगी है। मौसम बदलने से उल्टी, दस्त, बुखार जैसी बीमारियां ज्यादा पनप रही हैं। झोलाछाप डॉक्टर द्वारा बीमारियों का फायदा उठाकर मरीजों को जमकर लूटा जा रहा है।

दिखावे की होती है कार्यवाही

झोलाछाप डॉक्टरों के धंधे की जानकारी प्रशासन को भी है। समय-समय पर एक-दो क्लीनिक में छापा मारकर खानापूर्ति कर ली जाती है। काफी झोलाछाप तो ऐसे हैं, जिन्होंने खुद को बंगाली डॉक्टर, वैद्य, हकीम व अन्य डिग्री धारक घोषित कर रखा है। स्वास्थ्य विभाग कभी इनकी डिग्रियों की जांच नहीं करता। कई के पास दूर-दूर के राज्यों से जारी फर्जी डिग्रियां हैं। कई बार तो बंगाली चिकित्सा पद्धति के नाम पर उक्त झोलाछाप लोगों की जान से खिलवाड़ करने तक से नहीं चूकते। मजे की बात तो यह है कि दिखावे की होने वाली कार्यवाही के कुछ दिनों बाद कैसे उक्त संस्थान दोबारा खुल जाते हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है प्रमुख कारण

झोलाछाप डॉक्टरों की लगातार बढ़ती संख्या के लिए सरकारी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। वहीं विभाग द्वारा झोलाछाप पर कार्रवाई न होना भी बढ़ा कारण है। झोलाछाप डॉक्टर पहले उल्टा सीधा इलाज करते हैं। इसके बाद जब स्थिति काबू से बाहर हो जाती है, तो किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने के नाम पर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। हालांकि, तब तक स्थिति यह हो जाती है कि मरीज को बचाया जाना संभव ही नहीं रहता है।ये डॉक्टर बुखार की जांच के लिए कोई भी टेस्ट तक कराने की सलाह नहीं देते हैं। बिना प्रशिक्षण के लोगों को इंजेक्शन लगाने के साथ ग्लूकोज व अन्य दवाओं को चढ़ा देते हैं। दवा की डोज की सही जानकारी न होने के बावजूद सामान्य बीमारी में लोगों को दवा की हैवी डोज दे देते हैं। इसके चलते कई बार लोगों को एलर्जी व शारीरिक अपंगता तक हो जाती है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422